सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 218, नई दिल्ली, बुधवार 15 अक्टूबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन एक दर्पण की तरह है, यह आपको वही लौटाता है जो आप इसमें देखते हैं। ...

03 देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाया जा रहा 'स्मार्ट'...
06 उत्सव के पटाखे और वायु प्रदूषण शिशुओं की फेफड़ों को कैसे नुकसान...
08 "हरियाणा" के ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों एवं सारथी बंधुओं का खून-पसीना नहीं, बहता सैलाब

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा जनता, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के नाम से चलवाई जा रही बसे ब्ल्यू लाईन बसों से भी ज्यादा असुरक्षित ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली से प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा एसटीए परमिट पर चल रही ब्ल्यू लाईन बस स्कीम जिसमे वाहन मालिक अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के साथ जनता को सार्वजनिक बस सेवा प्रदान कर रहे थे को सड़को पर बस ऑपरेटरों द्वारा लालच का नाम देकर ख़तरा बनाने वाली सेवा कहते हुए सु मोटो लेकर केस चालू कर बंद करने के आदेश जारी कर उसके स्थान पर क्लस्टर स्कीम के तहत बसों को लाने के आदेश दे डाले थे।

आज दिल्ली की सड़को पर चल रही बसों जिसे स्वयं दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा जनता, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का नाम और लोगो लगाकर चलवाया जा रहा है के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाली दुर्घटनाएं क्या उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच रही ?

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के मैनेजमेंट द्वारा संचालित यह निजी कंपनियों की बसों के मालिकों को अब कौन सा लालच है जिसके तहत इनके द्वारा ब्ल्यू लाईन बसों से भी ज्यादा कहर सड़को पर बरसाया जा रहा हैं और सब कुछ देखते सुनते हुए भी उच्च न्यायालय है चुप, आखिर क्यों ?

क्यों नहीं उच्च न्यायालय स्वयं दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस से इन बसों द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाओं, हादसों और सड़को पर खराबी के कारण होने वाले जाम की रिपोर्ट लेकर कार्यवाही नहीं करना चाहता ?

दिल्ली में चल रही इन बसों के साथ नई शुरू की गई देवी बस सेवा से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। विनोद नगर डिपो तथा अन्य प्राइवेट डिपो से चलाई जाने वाली इन प्राइवेट कंपनियों की बसों द्वारा एक्सीडेंट हो रहे है जिसकी जानकारी सभी डिपो और मैनेजमेंट से दुर्घटना कि लिस्ट मांगने पर भी सामने आ सकती हैं और सबसे बड़ी बात गिनती सुनकर आप सभी आश्चर्य चकित रह जाएंगे।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की दिल्ली परिवहन निगम को खत्म कर उसकी संपत्तियों पर कब्जा करने की नीतियो के कारण दिल्ली की जनता को खुले आम मौत के हवाले किया जा रहा है और फिर भी दिल्ली के उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बैठे हैं चुप।

क्या उपराज्यपाल दिल्ली, उच्च न्यायालय दिल्ली और सर्वोच्च न्यायालय भारत इस लिए मौन है क्योंकि अब सड़को पर कहर बरसाने वाला कोई और नहीं स्वय दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की गलत नीतियां हैं और इन गलत नीतियों को लागू रखने के लिए उनका भी समर्थन दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को मिला हुआ है, बड़ा सवाल ?

दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप-1 में इस बार है बदलाव, उम्र पूरी कर चुके वाहनों और पटाखों पर लिया ये फैसला

दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप का पहला चरण लागू हो गया है। पुराने वाहनों पर रोक का अभियान हटा दिया गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पटाखों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन को लेकर भी निर्देशों में बदलाव किया गया है, अब कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सीएक्यूएम के अनुसार, कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से जंग में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों में से उम्रदराज वाहनों पर रोक सुनिश्चित करने की मुहिम को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी आदेश में इस बाबत कुछ नहीं कहा गया है।

गौरतलब है कि ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों में सबसे पहला निर्देश ही अपनी समयावधि पूरी कर चुके डीजल एवं पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाए जाने का है, लेकिन 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को उम्र के आधार पर सड़क से हटाने के मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।

मामला कोर्ट में चल ही रहा है तो सीएक्यूएम ने भी ग्रेप की पाबंदियों में कोई बदलाव न करने के बावजूद फिलहाल के लिए उक्त निर्देश को अपने आदेश से हटा लिया है। यानी पुराने वाहन अभी भी चलते रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

कमोबेश यही स्थिति पटाखों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन को लेकर है। ग्रेप के पहले चरण की कार्ययोजना में 19 नं. बिंदु पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से क्रियान्वित कराने से जुड़ा है।

पटाखों पर लागू प्रतिबंध के खिलाफ भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, तो सीएक्यूएम ने इस आशय के निर्देश की भाषा भी बदल दी है। आदेश में कहा गया है कि पटाखों को लेकर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रतिबंध शब्द हटा लिया गया है।

बातचीत में सीएक्यूएम के एक अधिकारी ने बताया कि जिन मामलों में राज्य सरकार सहमति नहीं रखती और कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है, उन्हें इस बार के आदेश में पूर्व की भांति शामिल नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा जैसा भी निर्णय कोर्ट लेगी, उसी के अनुरूप अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शुभ दीपावली" से लेकर बैंक-शून्य तक — त्योहारों पर बढ़ते फ्रॉड

[फेस्टिव फ्रॉड्स का महापर्व — जहाँ शुभकामना संदेश बनता है विनाश का दूत]

समय जैन
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)

कल्पना कीजिए, दीवाली की रात दीयों की झिलमिलाती रोशनी में आपकी नोटिफ़िकेशन टोन बजती है—एक परिचित नंबर से ₹शुभ दीपावली, ये खास गिफ्ट क्लेम करो₹ वाला मैसेज। उत्साह में क्लिक करते ही आपका बैंक खाता खाली, निजी डेटा चोरी। ये कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि भारत में हर त्योहार पर लाखों लोगों की हकीकत है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया (CERT-In, सर्ट-इन) की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, फेस्टिव सीजन में साइबर अटैक्स 45% उछाल मारते हैं, जहां फिशिंग लिंक्स और फेक मैसेजों से अरबों का नुकसान होता है। आरबीआई के अलर्ट्स बताते हैं कि यूपीआई फ्रॉड्स में 70% त्योहारों से जुड़े हैं। इस खतरे की गहराई समझें, क्योंकि सायबर चोरों की चालें मासूम शुभकामनाओं के पीछे छिपी होती हैं—और जागरूकता ही आपका अटल कवच है।

त्योहारों की भव्य चमक में सावधानी की लौ मद्धम पड़ जाती है—लोग आनंद के भंवर में खतरे को भूलकर लापरवाह हो जाते हैं। साइबर अपराधी इसी कमजोरी का घिनौना फायदा उठाते हैं। सबसे घातक जाल फिशिंग और स्मिशिंग: व्हाट्सएप पर ₹दीवाली स्पेशल लूट₹ का मोहक लिंक क्लिक होते ही नकली पोर्टल पर धकेल देता है, जहां बैंक आईडी, ओटीपी या यूपीआई पिन चुपके से उड़ा लिया जाता है। NCRB की 2023 साइबर अपराध रिपोर्ट सदमे से भर देती है—2 लाख से अधिक घटनाएं, करोड़ों की तबाही। कास्परस्की की वैश्विक जांच उजागर करती है कि भारत में 30% मैलवेयर घुसपैठ त्योहारों पर पीडीएफ या ज़िप फाइलों के बहाने होती है। ₹Diwali Blessings.zip₹ का जाल खोलते ही घातक वायरस घुसपठिए की तरह घुस जाता है, पृष्ठभूमि में डेटा लूटता रहता है—बैंक संतुलन से लेकर निजी स्मृतियों तक।

साइबर धूर्तों की धूर्तता आईडी क्लोनिंग में चरम पर - मित्र या स्वजन का व्हाट्सएप प्रोफाइल चुराकर ₹आपातकाल में 5000 रुपये भेजो₹ का भावुक जाल बिछाते हैं। इंटरपोल की 2024 चेतावनी इसे सर्वोच्च जोखिम वाला घोटाला घोषित करती है; भारत में असंख्य परिवार बर्बाद। क्यूआर कोड का फंदा और भी चालाक - डिजिटल आतिशबाजी या उपहार वाउचर के नाम पर स्कैन करवाते हैं, धन सीधे लुटेरों के खजाने में। आरबीआई के 2023 परिपत्र ने यूपीआई क्यूआर धोखों पर खतरे की घंटी बजाई—500 करोड़ से अधिक का विनाश। वॉइस घोटालों में नकली बैंक कॉलें—"रिफंड अटका है, ओटीपी सौंपो"—ट्रूकॉलर के 2024 आंकड़ों से 80% झूठी कॉलें त्योहारों की छत्रछाया में। नकली रिफंड लिंक पर उंगली पड़ते ही क्रेडिट कार्ड रहस्य उड़नतश्तरी। ये साधारण-सी चालें एक क्षणिक क्लिक से जीवन नष्ट कर देती हैं—सामान्य जन को इन्हें भेदना ही मुक्ति का मंत्र है।

सुरक्षा कोई मुश्किल पहाड़ी नहीं, बस रोजमर्रा की सावधानी की आदत डालें। पहला नियम: अज्ञात लिंक पर कभी क्लिक न करें; कोई ऑफर हो तो सीधे बैंक ऐप या आधिकारिक वेबसाइट से जाकर चेक करें—गूगल की सुरक्षा सलाह यही कहती है। ओटीपी, पासवर्ड या सीवीवी कभी किसी को न बताएं; आरबीआई साफ चेतावनी देता है—OTP शेयर करना अपराध है, असली बैंक या कंपनी फोन पर ये नहीं मांगती। संदिग्ध अटैचमेंट पर शक करें—सबसे पहले कॉल करके पुष्टि लें; माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट बताती है कि 85% वायरस इसी रास्ते से घुसते हैं। वेबसाइट का URL अच्छे से जांचें—HTTPS लॉक चिन्ह हो और सही डोमेन (जैसे paytm.co.in, न कि paytm-fake.net)। छोटे लिंक (जैसे bit.ly) को प्रीव्यू टूल से स्कैन करें; क्यूआर कोड से पहले ब्राउजर में लिंक चेक करें। यूपीआई के लिए सिर्फ आधिकारिक ऐप्स इस्तेमाल करें, तीसरे पक्ष के क्यूआर से दूर रहें।

हर खाते पर दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA) चालू रखें—एसएमएस से बेहतर ऐप-आधारित (जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर); सर्ट-इन की 2024 गाइड कहती है कि इससे 98% हैकिंग रुक जाती है। फोन या कंप्यूटर के अपडेट कभी न छोड़ें—ये सुरक्षा पैच कमजोरियों को जड़ से मिटाते हैं। मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड मैनेजर (जैसे बिटवॉर्डन) का इस्तेमाल करें। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों को साइबर सुरक्षा सिखाएं—यूनिसेफ स्टडी बताती है कि 60% पारिवारिक फ्रॉड में वे ही शिकार बनते हैं। त्योहारों पर 'बिना लिंक वाला मजा' का फैसला लें—खुशी मनाएं, लेकिन आंखें खुली रखें। ये छोटे-छोटे कदम त्योहारों को सुरक्षित जश्न बनाएंगे, नुकसान से दूर।

अगर गलती से लिंक पर क्लिक हो गया या फाइल खुल गई? घबराएं नहीं—तुरंत इंटरनेट बंद करें, एयरप्लेन मोड ऑन कर दें। इससे वायरस का फैलाव रुक जाता है, ईएफएफ की इमरजेंसी गाइड भी यही सलाह देती है। ओटीपी लीक हो गया? सभी पासवर्ड तुरंत बदलें, 2FA दोबारा सेट करें—ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है! पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं? बैंक हेल्पलाइन (जैसे SBI: 1800-11-2211) पर फोन करें, खाता फ्रीज करवाएं या पैसे वापस मांगें। आरबीआई का 24x7 फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम 40% मामलों में रिकवरी करा देता है। सबूत संभालें: स्क्रीनशॉट, चैट हिस्ट्री, नंबर—ये जांच में बहुत काम आते हैं। जल्दी रिपोर्ट करें: cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करें या लोकल साइबर सेल जाएं। एनसीआरबी 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 60% केस रिपोर्टिंग से सुलझ जाते हैं। फोन को अवास्ट या ईएसईटी एंटीवायरस जैसे भरोसेमंद एंटीवायरस से स्कैन करें; आखिरी चारा फैक्टरी रीसेट है, लेकिन पहले बैकअप लें। ये कदम नुकसान रोकेंगे और न्याय दिलाएंगे।

डिजिटल उपहार भेजने से पहले प्राप्तकर्ता से स्पष्ट पुष्टि लें। केवल प्रमाणित मंचों का मजबूत कवच बनाएं, ताकि धोखेबाजों के जालों से पूरी रक्षा हो। परिवार में 'साइबर रक्षक' की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करें। यह रक्षक हर संदिग्ध संदेश की गहन जांच करेगा और तुरंत खतरे की चेतावनी देगा—अलार्म बजा देगा। ऑनलाइन खरीदारी के लालच भरे जालों को आधिकारिक ऐप्स से कसकर जांचें। लोभ के फंदों में न फंसें, धूर्तों का मीठा जहर कभी न पिएं। सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बौछार करें, लेकिन स्थान या निजी जानकारी कभी न उजागर करें—दूसरों की नजरों का शिकार न बनें। सर्ट-इन की त्योहारी सुरक्षा सलाह ग्रुप चैट्स पर सख्त निगरानी का आदेश देती है। सावधानी की तेज रोशनी से दीवाली का पवित्र उजाला साइबर अंधेरे को चीर देगा। सुरक्षित उत्सव ही सच्ची जीत का जश्न है—डर के साए का पूरा सफाया।

डीटीसी बंद होने की कगार पर, प्राइवेट कंपनियों के भरोसे चल रही है दिल्ली परिवहन निगम

पंकज शर्मा

नई दिल्ली। डीटीसी के आखिरी बचे दो डिपो राजघाट और और नोएडा डिपो में 80% बसें हुई कबाड़, पिछले कुछ महीनो में दिल्ली की सभी सरकारी बसें हटाई गई हैं त्योहारी सीजन में बसों की कमी के कारण यात्रियों को बस नहीं मिल पा रही हैं, दिल्ली परिवहन निगम के सभी सरकारी डिपो बंद हो जाने के कारण रूट संख्या 33 पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता हैं, इसके बावजूद उन्हें बसें नहीं मिलती जिससे यात्रियों को ऑटो टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, सरकार प्राइवेट बसें लाने पर जोर दे रही है दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल से दिल्ली में एक भी दिल्ली परिवहन निगम की बसें नहीं ला पाई, सरकारी बसों के अभाव में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, और DTC की अपनी खुद की बसें बढ़ाने पर ही यात्रियों को राहत मिल सकती है जनवरी से अब तक कुल मिलाकर 2820 बसों को हटाया जा चुका है, जिस कारण लोगों को ऑटो टैक्सी में ज्यादा किराया देना पड़ रहा है 5 साल में यह पहली बार है जब दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में अपनी खुद की बसों की संख्या मात्र 149 रह गई है, जबकि प्राइवेट कंपनी डिम्ट्स के पास 2400 बसें हैं जिस कारण दिल्ली की भाजपा सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वर्तमान में दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है 1 पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में उचित योजना नहीं बनाए जाने के कारण बसों की संख्या में अचानक कमी आई, जनवरी 2026 तक दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में मात्र 20 बसें रहेंगी 1 आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका सरकार DTC के बेड़े में अपनी बसें लाई जाए और यह सुनिश्चित करें कि ज्यादा सवारी वाले रूटों पर ज्यादा बसें लगाई जाएं इस तरह दिल्ली की जनता को राहत मिल सकती है

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।

A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुँचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution,

Getting children free education,

हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

SCAN ME

If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.

हमें सपोर्ट करें और एक आवाज़ बनें इस बदलाव की।

Together, let's serve. Together, let's change.

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,

www.tolwa.com/member.html

स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,

वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

श्री सिद्धवट मंदिर

उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्रचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू मान्यता अनुसार चार वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, वंशीवट, बौधवट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। इस वटवृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे का तवा जडवा दिया गया था, परंतु कोई भी इसको पुनः फुटने से रोक नहीं पाया एवं यह फिर से हरा-भरा हो गया था। यह एक घाट पर स्थित है जहां पर पित्रुओं के लिए श्राद्धकर्म किये जाते है। इस स्थान पर शिवलिंग भी स्थित है, जिसे पातालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर एक शिला है जिसको प्रेत-शीला के नाम से जाना जाता है।

स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यहीं उन्होंने तारकासुर का वध किया था। संसार में केवल चार ही पवित्र वट वृक्ष हैं। प्रयाग (इलाहाबाद) में अक्षयवट, मथुरा-वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौधवट भी कहा जाता है और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्धवट हैं।

यहाँ तीन तरह की सिद्धि होती है संतति, संपत्ति और सद्‍गति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। सद्‍गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बाँधा जाता है और संतति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा सातिया (स्वस्विक) बनाया जाता है। यह वृक्ष तीनों प्रकार की सिद्धि देता है इसीलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है।

यहाँ पर नागबलि, नारायण बलि-विधान का विशेष महत्व है। संपत्ति, संतित और सद्‍गति की सिद्धि के कार्य होते हैं। यहाँ पर कालसर्प शांति का विशेष महत्व है, इसीलिए कालसर्प दोष की भी पूजा होती है। वर्तमान में इस सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्षकर्म, पिंडदान, कालसर्प दोष पूजा एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है।

इस स्थान पर एक प्राचीन वटवृक्ष है जो कि बहुत प्रसिद्ध वटवृक्ष है। इस वटवृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे का तवा जडवा दिया गया था, परंतु कोई भी इसको पुनः फुटने से रोक नहीं पाया एवं यह फिर से हरा-भरा हो गया था। यह एक घाट पर स्थित है जहां पर पित्रुओं के लिए श्राद्धकर्म किये जाते है। इस स्थान पर शिवलिंग भी स्थित है, जिसे पातालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर एक शिला है जिसको प्रेत-शीला के नाम से जाना जाता है।

तीर्थ स्थली उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित सिद्धवट का वही महत्त्व है जो गया तथा प्रयाग में अक्षयवट का है. स्कंद्पुरण के अवन्तिखंड में वर्णन है की देवाधिदेव महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के बाद अपनी शक्ति यहाँ शिप्रा में फेंकी थी जो पाताल में चली गई इसलिए इसे शक्तिभेद तीर्थ भी कहते हैं. जगत्जननी माता पारवती ने इसी वाट के निचे अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय को भोजन कराया था. भगवान-शिव ने वट वृक्ष आशीर्वाद दिया की तुम संसार में कल्प के रूप में जाने जाओ. सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ तपस्या करके अग्या बेताल की सिद्धि की थी. इस मंदिर में स्थित शिवलिंग (पतालिश्वर) का लिंग जलधारी की सतह से निचे है. कहा जाता है की जैसे जैसे प्रथ्वी पर पाप बढ़ता है यह धंसता चला जाता है. मंदिर क्षिप्रा के तट पर ही है जहाँ पक्के घाट बने हुए हैं.मुग़ल शासकों ने इस वृक्ष को कटवा कर लोहे के तवे मढवा दिए थे, पर उन लौह पत्रों को छेड़ कर वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया।

काल के भी काल महाकाल

जो ईश्वर का भक्त होता है, उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर काल (मृत्यु) का अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से काल की भी मृत्यु हो जाती है।

गोदावरी के तट पर 'श्वेत' नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर साम्ब सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था।

वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर - सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था।

उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था।

उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था।

यमदूत समय से उन्हें लेने आएं, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे।

चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा - मृत्युदेव ! श्वेत ब्राह्मण अब तक यहां क्यों नहीं आया ? तुम्हारे दूत भी नहीं आएं।

यह सुनकर काल (मृत्युदेव) को श्वेत ब्राह्मण पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े।

घर के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखायी पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा - नाथ ! हम क्या करें ? श्वेत तो भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है। उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है ।

दूतों की बात सुनकर काल (मृत्युदेव) का क्रोध और भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहां क्या हो रहा है ?

काल (मृत्युदेव) को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा - मृत्युदेव ! आप लौट जाइये। किंतु काल (मृत्युदेव) ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया।

भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने काल (मृत्युदेव) पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंड हो गए।

यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर - थर कांप रहे थे। काल (मृत्युदेव) की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया।

उन्होंने हाथ में यमदण्ड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत ब्राह्मण के घर पहुंच गए।

वहां भगवान भोलेनाथ के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गयी।

यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उन सबके साथ घटनास्थल पर आये।

देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और कहा - भोले नाथ ! यमराज सूर्य के पुत्र हैं।

ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो जायगी।

भोलेनाथ ! आप से की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती।

भगवान आशुतोष ने कहा - मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं।

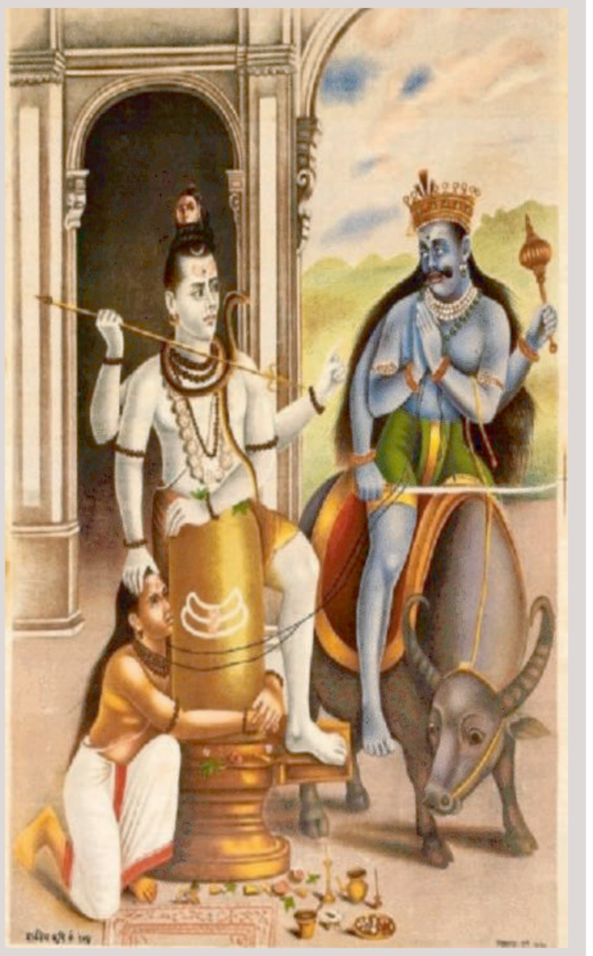

वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम ही होते हैं। काल (मृत्यु) का उन पर कोई अधिकार नहीं होता।

यमराज के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें।

इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा (गोदावरी) का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए..!!

इसलिए भगवान भोले नाथ को कालो का काल महाकाल कहा जाता है

कार्तिक की कहानियाँ (राम-लक्ष्मण की कहानी)

भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया–एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल-फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने चार पत्तल परोसी तब लक्ष्मण ने पूछा–'भाभी माँ हम तीन हैं फिर चार में क्यों परोसा ?' माँ सीता बोली–'एक पत्तल गों माता की हैं।'

जब राम जी, लक्ष्मण जी, और गोमाता को पत्तल परोस दी तब राम जी ने पूछा–'सीता जी आप ने खाना शुरू क्यों नहीं किया ?' सीता माँ बोली–'मेरे तो राम कथा सुनने का नियम हैं राम कथा सुनने के बाद ही में फल ग्रहण करूँगी।'

रामजी बोले–'मुझे कथा सुना दो', लक्ष्मण जी बोले–'मुझे सुना दो' तब माँ सीता बोली–'औरत की बात औरत ही सुने–आप मेरे आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो आपसे कैसे कहूँ ?'

लक्ष्मणजी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी ? फिर लक्ष्मणजी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजे सोने की थीं इसलिये नगरी का नाम सोन नगरी रखा।

सभी नगर निवासियों को घमण्ड हो गया उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुँऐ पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम-राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम-राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या ?' वह बोली–'मेरे तो घर पर काम हैं।' सीता जी ने कहा–'मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं।' लडकी बोली–'मेरी माँ मेरा इन्तजार कर रही हैं।'

वह लडकी वहाँ से जानी लगी तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लडकी घर गई तो माँ बोली–'बाई ये क्या हुआ ?' तब लडकी बोली–'मेरे को तो पता नहीं हैं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं।'

तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लडकी ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया तब उसकी बहु बोली–'आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन कर आती हूँ।'

जब बहु कुँऐ पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीताजी ने कहा–'आपके घर पर कुछ काम नहीं हैं क्या ?' वह बोली माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूँ।' माँ सीता बोली–'तू मुझे माँ कहकर बुलाई यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कहानी सुन लेगी ?' वह बोली–'माताजी कहानी सुनाओ मैं प्रेम से कहानी सुनूँगी।'

सीताजी ने कहा–'हे बाई ! तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे।'

राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा–'हे बाई ! तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की राम जी लक्ष्मण को जिमाया हैं भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे। तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा।' सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गयी तो उसके मटके सब सोने के हो गये। सासु जी ने कहा–'ये सब तू कहाँ से लाई ?'

बहु बोली–'मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी ये इसी का फल हैं।' सासुजी ने कहा–'प्रतिदिन राम कथा सुन आना।'

बहु को रामकथा सुनते बहुत दिन हो गये तब उसने माँ सीता से पूछा–'इसका उद्यापन विधि बतलाओ।' तब सीता जी ने कहा–'सात लड्डू लाना, एक नारियल लाना उसके सात भाग करना, एक भाग मन्दिर में चढ़ाना जिससे मन्दिर बनवाने जितना फल होता है। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भगवद्गीता पर चढ़ाना जिससे भगवद्गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कुँवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा।'

बहु ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली–'माता मैंने तो विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया।' सीता जी ने कहा–'अब सात दिन बाद वैकुण्ठ से विमान आएगा।'

सात दिन पूरे हुए विमान आया तो बहु ने कहा–'सासुजी स्वर्ग से विमान आया है।' सासुजी ने कहा–'बहु तेरे ससुरजी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल सारे कुटुम्ब परिवार को ले चल, अड़ोसी-पड़ोसियों को ले चल।' बहु ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था।

थोड़ी देर में उसकी नन्द आई और देखते-ही-देखते विमान भर गया। तब बहु ने कहा–'माँ सीता नन्द बाईसा को भी बिठा लो।' माँ सीता ने कहा–'इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया।' बहु ने कहा–'बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना उसके बाद आप के लिए वैकुण्ठ से विमान आएगा।'

गाँव के सारे लोग एकत्र हो गये और पूछने लगे–'बाई तूने ऐसा कौन-सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओं ?' बहु ने कहा–'मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया।'

तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद्द करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर-नारी सुनने लगे, राम कथा सम्पूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा–'जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा।'

सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। सात स्वर्ग के दरवाजे खुल गये। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे देवताओं ने पूछा–'तूने क्या पुण्य किया ?' बहु ने कहा–'मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी।' समस्त देवताओं ने कहा–'वर मांग।' तब वह बोली–'मेरे पास सब सिद्धियाँ हैं। मुझे यह वर दो की जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले।'

सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों और राम-राम की जय जयकार होने लगी।

डॉ0 विजय शंकर मिश्र:

तीन औषधियों का ये मिश्रण इन 18 असाध्य रोगों का काल है., बुढ़ापे में भी रहेगी जवानी...।।

बार बार रोगी उपचार हेतु एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाता है. एलोपैथिक उपचार करवाने पर भी जब उसे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिखता, वह आयुर्वेदिक उपचार की ओर मुडता है।आयुर्वेदिक उपचार करवाने के उपरांत रोगी को रोग ठीक होने का भान होता है।

तब वह यह विचार करने लगता है, कि अच्छा होता यदि मैं आरंभ से ही आयुर्वेदिक उपचार करवाता।

इसलिए ऐसा ना हो तथा हानिकारक दुष्प्रभावों से बचने के लिए, रोग के आरंभ में ही आयुर्वेदिक उपचार करवाना आवश्यक है।

•••

इन 3 औषधियों की बहुत उपयोगी दवा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री :

250 ग्राम मैथीदाना

100 ग्राम अजवाईन

50 ग्राम काली जीरी (ज्यादा जानकारी के लिए नीचे देखे)

तैयार करने का तरीका :

उपरोक्त तीनो चीजों को साफ-सुथरा करके हल्का-हल्का सेंकना (ज्यादा सेंकना नहीं) तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके मिक्सर में पावडर बनाकर कांच की शीशी या बरनी में भर लेवें।

औषधि को सेवन करने का तरीका,,,,,

रात्रि को सोते समय एक चम्मच पावडर एक गिलास पूरा कुन-कुना पानी (हल्का गर्म) के साथ लेना है। गरम पानी के साथ ही लेना अत्यंत आवश्यक है लेने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह चूर्ण सभी उम्र के व्यक्ति ले सकतें है।

चूर्ण रोज-रोज लेने से शरीर के कोने-कोने में जमा पडी गंदगी (कचरा) मल और पेशाब द्वारा बाहर निकल जाएगी । पूरा फायदा तो 80-90 दिन में महसूस करेगें, जब फालतू चरबी गल जाएगी, नया शुद्ध खून का संचार होगा। चमड़ी की झुर्रियॉ अपने आप दूर हो जाएगी। शरीर तेजस्वी, स्फूर्तिवाला व सुंदर बन जायेगा ।

इन 18 रोगों में फायदेमंद है,,,,

गठिया दूर होगा और गठिया जैसा जिद्दी रोग दूर हो जायेगा।

हड्डियाँ मजबूत होगी।

आँखों रौशनी बढ़ेगी।

बालों का विकास होगा।

पुरानी कब्जियत से हमेशा के लिए मुक्ति।

शरीर में खुन दौड़ने लगेगा।

कफ से मुक्ति।

हृदय की कार्य क्षमता बढ़ेगी।

थकान नहीं रहेगी, घोड़े की तहर दौड़ते जाएगें।

स्मरण शक्ति बढ़ेगी।

स्त्री का शरीर शादी के बाद बेडोल की जगह सुंदर बनेगा।

कान का बहरापन दूर होगा।

भूतकाल में जो एलॉपेथी दवा का साईड इफेक्ट से मुक्त होगें।

खून में सफाई और शुद्धता बढ़ेगी।

शरीर की सभी खून की नलिकाएं शुद्ध हो जाएगी।

दांत मजबूत बनेगा, इनेमल जींवत रहेगा।

शारीरिक कमजोरी दूर तो मर्दाना ताक़त बढ़ेगी।

डायबिटिज काबू में रहेगी, डायबिटीज की जो दवा लेते है वह चालू रखना है। इस चूर्ण का असर दो माह लेने के बाद से दिखने लगेगा।

जिंदगी निरोग, आनंददायक, चिंता रहित स्फूर्ति दायक और आयुष्यवर्धक बनेगी। जीवन जीने योग्य बनेगा।

कृपया ध्यान दे :

कुछ लोग कलौंजी को काली जीरी समझ रहे है जो कि गलत है काली जीरी अलग होती है जो आपको पंसारी या आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगी, यह स्वाद में हल्की कड़वी होती है, नीचे जो

फोटो है वो कालीजीरी (Purple Fleabane) का है, जिसका नाम अलग-अलग भाषाओं में कुछ इस तरह से है।

हिन्दी कालीजीरी, करजीरा।

संस्कृत अरण्यजीरक, कटुजीरक, बृहस्पाती।

मराठी कडूकारेलें, कडूजीरें।

गुजराती कडबुंजीरू, कालीजीरी।

बंगाली बनजीरा।

अंग्रेजी पर्पल फ्लीबेन

कालीजीरी –

कालीजीरी को आयुर्वेद में सोमराजि, सोमराज, वनजीरक, तिक्तजीरक, अरण्यजीरक, कृष्णफल आदि नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में इसे कालीजीरी, बाकची और बंगाल में सोमराजी कहते हैं।

कालीजीरी किसी भी तरह के जीरे से अलग है। इंग्लिश में इसे पर्पल फ़्लीबेन कहते हैं पर यह कलोंजी Nigella sativa से बिल्कुल भिन्न है। कलोंजी को भी इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन ही कहते है। इसी प्रकार बाकची, या सोमराजी एक और पौधे के बीज को, सोरेला कोरीलिफ़ोलिया (Psoralea corylifolia) को कहते है।

आयुर्वेद के बहुत से विशेषज्ञ सोरेला कोरीलिफ़ोलिया को ही बावची या सोमराजी मानते हैं पर बंगाल में कालीजीरी को सोमराजी नाम से जानते और प्रयोग करते हैं।

कालीजीरी स्वाद में कड़वा और तेज गंद्ध वाला होता है, इसलिए इसे किसी भी तरह के भोजन बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। इसको केवल एक दवा की तरह ही प्रयोग किया जाता है। लैटिन में इसका नाम, सेंट्राथरम ऐनथेलमिंटिकम या वरनोनिया ऐनथेलमिंटिकम है।

इसके वैज्ञानिक नाम में 'ऐनथेलमिंटिकम' इसके प्रमुख आयुर्वेदिक प्रयोग को बताता है। ऐनथेलमिंटिकम का मतलब है, शरीर से परजीवियों को नष्ट करने वाला। आयुर्वेद में इसे कृमिनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है।

इसका सेवन और बाह्य प्रयोग चर्म रोगों के इलाज, जैसे की श्वित्र (leukoderma) सफ़ेद दाग, खुजली, एक्जिमा, आदि। इसे सांप या बिच्छु के काटे पर भी लगाते हैं। कालीजीरी का क्षुप, पूरे देश में परती जमीन पर पाया जाता है। इसके पत्ते शल्याकृति किनारेदार होते हैं। बारिश के मौसम के बाद इसमें मंजरी निकलती है। जिसमे काले बीज आते है।

काली जीरी आकार में छोटी और स्वाद में तेज, तीखी होती है। इसका फल कडुवा होता है। यह पौष्टिक एवं उष्ण वीर्य होता है। यह कफ, वात को नष्ट करती है और मन व मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं और खून साफ होता है। त्वचा की खुजली और उल्टी में भी इसका प्रयोग लाभप्रद होता है।

यह त्वचा के रोगों को दूर करता है, पेशाब को लाता है एवं गर्भाशय को साफ व स्वस्थ बनाता है। यह सफेद दाग (कुष्ठ) को दूर करने वाली, घाव और बुखार को नष्ट करने वाली होती है। सांप या अन्य विषैले जीव के डंक लगने पर भी इसका प्रयोग लाभकारी होता है।

कालीजीरी के 13 फायदे :

यह कृमिनाशक और विरेचक है।

यह गर्म तासीर के कारण श्वास, कफ रोगों को दूर करती है।

मूत्रल होने के कारण यह मूत्राशय, की दिक्कतों और ब्लड प्रेशर को कम करती है।

यह हिचकी को दूर करती है।

यह एंटीसेप्टिक है चमड़ी की बिमारियों जैसे की खुजली, सूजन, घाव, सफ़ेद रोग, आदि सभी में बाह्य रूप से लगाई जाती है।

जंतुघ्न होने के कारण शरीर के सभी प्रकार के परजीवियों को दूर करती है।

काली जीरी को चमड़ी के रोगों में नीम के काढ़े के साथ मालिश या खादिर के काढ़े के आंतरिक प्रयोग के साथ करना चाहिए।

भयंकर चमड़ी रोगों में, काली जीरी + काले तिल बराबर की मात्रा में लेकर, पीस कर 4 ग्राम की मात्रा में सुबह, एक्सरसाइज की बाद पसीना आना पर लेना चाहिए। ऐसा साल भर करना चाहिए।

श्वेत कुष्ठ जिसे सफ़ेद दागभी कहते है, उसमे चार भाग काले जीरी और एक भाग हरताल को गोमूत्र में पीसकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इसी को काले तिलों के साथ खाने को भी कहा गया है। (भैषज्य रत्नावली)

पाइल्स या बवासीर में, 5 ग्राम कालाजीरालेकर उसमे से आधा भून कर और आधा कच्चा पीसकर, पाउडर बनाकर तीन हस्से कर के दिन में तीन बार खाने से दोनों तरह की बवासीर खूनी और बादी में लाभ होता है।

पेट के कीड़ों में इसके तीन ग्राम पाउडर को अरंडी के तेल के साथ लेना चाहिए।

खुजली में, सोमराजी + कासमर्द + पंवाड़ के बीज + हल्दी + दारुहल्दी + सेंधा नमक को बराबर मात्रा में मिलकर, कांजी में पीसकर लेप लगाने से कंडू, कच्छु (खुजली) आदि दूर होते हैं।

कुष्ठ में, कालीजीरी + वायविडंग + सेंधानमक + सरसों + करंज + हल्दी को गोमूत्र में पीस कर लगना चाहिए।

कालीजीरी के सेवन की मात्रा :

इसको 1-3 ग्राम की मात्रा में लें। इससे अधिक मात्रा प्रयोग न करें।

आवश्यक सावधानियाँ :

कृमिनाशक की तरह प्रयोग करते समय किसी विरेचक का प्रयोग करना चाहिए।

कालीजीरी के प्रयोग में सावधानियां

यह बहुत उष्ण-उग्र दवा है।

गर्भावस्था में इसे प्रयोग न करें।

यह वमनकारक है।

अधिक मात्रा में इसका सेवन आँतों को नुकसान पहुंचाता है।

यदि इसके प्रयोग के बाद साइड इफ़ेक्ट हों तो गाय का दूध / ताजे आंवले का रस / आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए।।।।।।

गर कोई आसपास आयुर्वेदिक का जानकर हो तो उसके मार्गदर्शन में इस्तेमाल करिए आपको सौ प्रतिशत लाभ मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आज

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।

यह दिन इस बात पर ज़ोर देता है कि ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के बिना दुनिया का स्थायी भविष्य संभव नहीं है। चूँकि ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक-आर्थिक बदलाव की सक्रिय वाहक हैं, इसलिए उन्हें देखभाल की रूढ़िवादी भूमिका से बाहर निकालने की ज़रूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की पृष्ठभूमि

==========================

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में नागरिक समाज संगठनों द्वारा की गई थी। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 को अपने प्रस्ताव 62/136 के माध्यम से आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया था।

ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय

दिवस का महत्व

==============================

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह दिवस कृषि-आधारित नौकरियों में इन महिलाओं के सामने आने वाले कई लैंगिक भेदभावों के बारे में बात करता है। यह दिवस विश्व भर में ग्रामीण महिला नेताओं और उनके समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर की महिला समूहों के सम्मान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य यह उजागर करना है कि यद्यपि ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी वे ग्रामीण पुरुषों और शहरी महिलाओं से पीछे हैं। यह दिवस इन महिलाओं के संघर्षों, उनकी ज़रूरतों और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस प्रकार, यह स्थापित करता है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है।

मीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

==============================

यद्यपि ग्रामीण महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के समान अधिकार और हिस्सेदारी प्राप्त नहीं है।

उन्हें समान वेतन, ऋण, निर्णय लेने में भागीदारी, संसाधनों तक पहुंच और पशुधन स्वामित्व में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुँच भी बहुत कम है। प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता भी ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सीमित करती है।

बहुत सी ग्रामीण महिलाएं अलगाव और अपने कार्य तथा व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की कमी से पीड़ित हैं।

खनन क्षेत्र में ममता पर गरीबी हावी — मां ने नवजात पुत्र को 50 हजार में बेचा, पकड़े जाने के डर से हुई फरार

कोईडा खनन क्षेत्र की मानवीय त्रासदी, सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाला इलाका अब सामाजिक पतन का प्रतीक – डॉ राजकुमार यादव

राउरकेला/कोईड़ा (सुंदरगढ़):

ओडिशा का कोईडा खनन क्षेत्र, जो राज्य सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपये का राजस्व देता है, आज सामाजिक और मानवीय पतन का प्रतीक बन चुका है। यहां गरीबी और अभाव ने लोगों को इस कदर तोड़ दिया है कि एक मां ने अपने नवजात पुत्र को मात्र 50 हजार रुपये में बेच दिया।

घटना सुंदरगढ़ जिले के कोईडा ब्लॉक के पाटमुंडा हाटिंग गांव की है। स्थानीय महिला पार्वती लुगुन ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी के कारण अपने नवजात पुत्र को 50 हजार रुपये में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, और अब पकड़े जाने के डर से वह अपने घर से फरार है।

घटना का खुलासा — आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सजगता से सामने आया मामला

जानकारी के अनुसार, पार्वती लुगुन गर्भवती होने के बाद 8 अगस्त को कोईडा स्थित "मां गृह" में भर्ती हुई थीं।

उन्हें प्रसव के लिए राउरकेला सरकारी अस्पताल (RGH) भेजा गया, जहां 31 अगस्त को उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। अगले दिन डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने पहले से तय सौदे के तहत बच्चे को घर न ले जाकर रास्ते में ही 50 हजार रुपये में बेच दिया।

पहली किस्त के रूप में उसने 25 हजार रुपये प्राप्त किए थे।

घर लौटने पर जब आशा कार्यकर्ता मागदली नायक ने बच्चे के बारे में पूछा तो पार्वती ने टालमटोल किया।

इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला दास जब टीकाकरण के लिए बच्चे को देखने गईं, तो बच्चा घर में नहीं मिला।

डॉ राजकुमार यादव

दोनों ने इस संदिग्ध स्थिति की जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) अनीता साहू को दी।

CDPO की कार्रवाई — जांच टीम गठित, बच्चे को वापस लाने का प्रयास जारी

घटना की जानकारी मिलते ही CDPO अनीता साहू स्वयं टीम के साथ पार्वती के घर पहुंचीं। पूछताछ में पार्वती ने यह स्वीकार किया कि उसने बच्चे को बेच दिया है, लेकिन यह बताने से इंकार कर दिया कि उसने उसे किस व्यक्ति या परिवार को बेचा है।

इसके बाद प्रशासन ने त्वरित जांच शुरू की है। CDPO ने कहा —

"यह अत्यंत चिंताजनक और अमानवीय घटना है। हमने जांच टीम गठित कर दी है और बच्चे को शीघ्र बरामद कर सुरक्षित स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।"

घटना के उजागर होने के बाद पार्वती और उसका पति दोनों घर से फरार हैं।

उनकी सास और चार छोटे बच्चे अब पाटमुंडा स्थित झोपड़ीनुमा घर में मां के लौटने की राह देख रहे हैं।

खनन क्षेत्र की विडंबना — करोड़ों की आमदनी, पर लोगों की हालत बदहाल

कोईडा जैसे खनन क्षेत्र सरकार को कोटि-कोटि रुपये का राजस्व देते हैं, लेकिन यहां के मजदूरों और बस्तिवासियों की स्थिति अब भी बेहद दयनीय है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के तहत मिलने वाली सुविधाएं और सरकारी योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकल पाई हैं।

गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता ने यहां के लोगों को इंसानियत से दूर कर दिया है।

डॉ राजकुमार यादव ने कहा

"यह घटना केवल एक मां की लाचारी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है जो खनिज संपदा से समृद्ध इलाकों में भी मानवता को भूखा छोड़ रही है।

प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक जागरूकता और निगरानी तंत्र को मज़बूत करे।"

सूचना का अधिकार के बीस साल : आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी क्रांति के सामने कई चुनौतियां

राजेश जैन

साल 2005 में जब देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ तो लगा जैसे लोकतंत्र की असली धड़कन मिल गई हो। सरकारी फाइलों के बंद दरवाज़े आम जनता के सामने खुलने लगे। इसके ज़रिए एक साधारण नागरिक भी किसी अधिकारी से पूछ सकता था—आपने यह फैसला कैसे लिया? यह कानून सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं था बल्कि सरकार से जनता की ओर शक्ति का पुनर्वितरण था।

एक अनुमान के अनुसार हर साल भारत में लाखों आरटीआई आवेदन दाखिल होते हैं। इन आवेदनों के ज़रिए न सिर्फ़ भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हुआ बल्कि राशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा, पेंशन, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच भी बढ़ी। कोविड महामारी के दौरान जब अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की जानकारी के लिए लोग भटक रहे थे, तब यही कानून था जिसने कई जगह सरकारी डेटा सार्वजनिक कराया और जानें बचीं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का हथियार है आरटीआई

राइट टू इन्फॉर्मेशन (आरटीआई) एक्ट ने बड़े-बड़े घोटालों को उजागर किया — व्यापम, आदर्श हाउसिंग, चुनावी बांड और कई बैंकिंग घोटाले जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक तक को अपने रिकॉर्ड सार्वजनिक करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कौन से उद्योगपति बैंकों का कर्ज़ नहीं चुका रहे हैं। दरअसल, इस कानून ने जनता को बोलने की ताकत दी और सत्ता को जवाब देने की ज़िम्मेदारी लेकिन जब आम जनता ने सवाल पूछने शुरू किए तो सत्ताएं असहज होने लगीं। यही असहजता अब धीरे-धीरे इस कानून को कमजोर करने के रूप में सामने आ रही है।

कमज़ोर होते सूचना आयोग

सूचना आयोग आरटीआई की रीढ़ हैं। यही संस्थाएं नागरिकों की अपील सुनती हैं जब उन्हें सरकारी विभाग से जवाब नहीं मिलता लेकिन अब ये आयोग खुद ही सूचना-विहीन होते जा रहे हैं। सतर्क नागरिक संगठन की 2023–24 की रिपोर्ट बताती है कि देश के 29 में से 7 आयोग कई महीनों तक निष्क्रिय रहे। केंद्रीय सूचना आयोग में कई बार तब तक आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई जब तक जनता कोर्ट नहीं गई। झारखंड में तो आयोग पांच साल से करीब-करीब ठप पड़ा है। ऐसे में देशभर में 4 लाख से ज़्यादा आरटीआई मामले लंबित हैं। कई आयोगों में सुनवाई के लिए एक साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। जब सूचना इतनी देर से मिले कि उसका मतलब ही खत्म हो जाए तो यह सूचना देना नहीं बल्कि सूचना छीन लेना कहलाता है।

आज़ादी पर शिकंजा: 2019 का संशोधन

आरटीआई कानून ने सूचना आयुक्तों को एक हद तक स्वतंत्रता दी थी— उनका कार्यकाल तय, वेतन संरक्षित और दर्जा संवैधानिक था लेकिन 2019 में संसद में पारित आरटीआई संशोधन अधिनियम ने इस पूरी संरचना को हिला दिया। अब आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और रिटायरमेंट लाभ तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सोचिए, जिसे आपकी निगरानी रखनी है, उसका भविष्य अगर आपके हाथ में हो, तो क्या वह ईमानदारी से आपकी गलतियों को उजागर करेगा? यह संशोधन ऐसा है जैसे प्रहरी के हाथों से उसकी सीटी छीन लेना। कानून अब भी मौजूद है पर उसकी आत्मा सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रही है।

निजी कहकर सार्वजनिक जानकारी पर ताला

2023 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया—डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कहा गया कि यह नागरिकों की निजता की रक्षा करेगा पर इसके तहत आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जे) में संशोधन कर दिया गया जिससे अब कोई भी ₹निजी जानकारी₹ सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी। पहले यह छूट सीमित थी—निजी जानकारी तभी रोकी जाती थी जब उसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध न हो। अब यह एक खुला दरवाज़ा बन गया है जिसके ज़रिए "निजी" कहकर बहुत सी सार्वजनिक जानकारी भी छिपाई जा सकती है जैसे कर्ज़ न चुकाने वालों के नाम, चुनावी बांड खरीदने वालों की जानकारी, वोटर लिस्ट, अफसरों की संपत्ति या ठेकों में शामिल कंपनियां। यह वही पारदर्शिता थी जो लोकतंत्र की आत्मा थी और अब निजता के नाम पर उस पर पर्दा डाल दिया गया है। नतीजा यह कि जनता के नाम पर शासन करने वाली व्यवस्था अब जनता से छिपकर काम कर सकती है।

जवाबदेही से बचने का नया बहाना — "नो डेटा अवेलेबल"

पिछले कुछ वर्षों में सरकार के जवाबों में एक वाक्य बार-बार सुनाई देने लगा है—₹नो डेटा अवेलेबल₹। कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुईं, किसानों ने आत्महत्या क्यों की, नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, आपदाओं के नुकसान, बेरोज़गारी के सही आंकड़े — सब कुछ एक ही जवाब में गुम हो गया: "डेटा उपलब्ध नहीं है।" सोचिए, जिस देश में सरकार के पास डेटा नहीं, वहां की जनता जवाब कैसे मांगेगी? डेटा की अनुपलब्धता अब जवाबदेही से बचने की दीवार बन चुकी है और यह दीवार हर गुजरते साल के साथ ऊंची होती जा रही है।

सूचना मांगने वालों पर जानलेवा खतरा

आरटीआई कानून ने आम नागरिकों को आवाज़ दी पर यह आवाज़ कई बार उनकी जान की कीमत पर आई। देश में अब तक करीब 100 व्हिसलब्लोअर सूचना मांगने या भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण मारे जा चुके हैं। 2014 में व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था पर नौ साल बाद भी यह लागू नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि जो नागरिक सच्चाई उजागर करता है, वह अकेला पड़ जाता है, असुरक्षित हो जाता है। सत्ता की परतें जितनी अपारदर्शी होती जाती हैं, सच बोलने वालों पर उतनी ही मोटी छाया पड़ती है।

कानून नहीं, भावना बचानी होगी

आरटीआई एक्ट सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, यह लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि सरकार जनता की है, जनता सरकार की नहीं। अगर यह विश्वास टूट गया, तो संविधान की सारी धाराएं भी हमें पारदर्शी शासन नहीं दे पाएंगी। आज चुनौती यह है कि हम कानून के शब्दों को नहीं, उसकी भावना को ज़िंदा रखें। कानून कमजोर हो सकता है, पर नागरिक की जिज्ञासा नहीं। सूचना आयोग निष्क्रिय हो सकते हैं, पर जनता के सवाल नहीं रुकने चाहिए। व्हिसलब्लोअर मारे जा सकते हैं पर सच्चाई की लौ बुझनी नहीं चाहिए।

लोकतंत्र में पारदर्शिता विलासिता नहीं, अनिवार्यता है

आरटीआई के 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच सरकारें बदलीं, नेता बदले, पर जनता आज भी जानकारी पाने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। आज जरूरत है कि हम इस कानून को बचाने के लिए फिर से उतनी ही ऊर्जा, उतना ही जुनून जुटाएं, जितना 2005 में था—क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता कोई विलासिता नहीं, अनिवार्यता है। अगर जानकारी का दरवाज़ा बंद हो गया, तो जनता सिर्फ़ दर्शक बनकर रह जाएगी। और याद रखिए—जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है, वह धीरे-धीरे गुलाम बन जाता है। आरटीआई की यह लौ बुझने नहीं देनी है, क्योंकि यही लौ हमें रोशनी देती है और बताती है कि सत्ता जनता की है और जनता को जानने का हक़ अब भी ज़िंदा है।

तालिबान को इतना महत्व क्यों दे रहा भारत

राजेश कुमार पासी

विदेश नीति के बारे में एक बात कही जाती है कि कोई भी आपका स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता. अगर कुछ स्थायी होता है तो वो आपके देश के हित होते हैं। अपने देश के हित के सामने सिद्धांत और नैतिकता की भी अनदेखी करनी पड़ती है। आपको अपनी नीतियां देश के हित को देखते हुए बनानी पड़ती है और समय-समय पर उसमें बदलाव करने होते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका सच्चा दोस्त होता है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन का पड़ोसी है. यही कारण है कि वो हमारा सच्चा दोस्त बन सकता है।

तालिबान पाकिस्तान की मदद से पैदा हुआ संगठन है जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए तैयार किया था। जब पिछली बार तालिबान सत्ता में आया तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रभाव में रहा जिसके कारण हमारे रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। वाजपेयी सरकार के दौरान 1999 में भारत का एक हवाई जहाज हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। तब भारत ने तालिबान से मदद मांगी थी लेकिन उसे मदद नहीं मिली। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को तीन कुख्यात आतंकवादियों को लेकर वहां जाना पड़ा ताकि यात्रियों को सुरक्षित वापिस लाया जा सके। 2021 में अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई है। शुरुआत में लगा कि ये पुराना तालिबान है तो भारत के लिए अफगानिस्तान में अब कोई जगह नहीं बची है। कहा जाने लगा कि भारत ने अफगानिस्तान में जितना भी निवेश किया है, सब बेकार चला गया है। भारत ने वहां अपना दूतावास भी बंद कर दिया और अपने नागरिकों को वापिस बुला लिया। धीरे-धीरे भारत को अहसास हुआ कि ये पुराना तालिबान नहीं है बल्कि ये एक बदला हुआ तालिबान है। देखा जाए तो

तालिबान की सोच और विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है लेकिन अब वो अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है।

तालिबान खुद भी एक आतंकवादी संगठन है लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद वो खुद को बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उसे अब एक देश को चलाना है और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। तालिबान दूसरे देशों के साथ संबंध बना रहा है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके और दुनिया में उसके शासन को मान्यता मिल सके। अमेरिका और चीन तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं जबकि उन्होंने भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। भारत भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है, उसने तालिबान को मान्यता नहीं दी है लेकिन उसके साथ संवाद स्थापित कर लिया है।

अब भारत ने तालिबान के साथ रिश्तों को नया आयाम देना शुरू कर दिया है क्योंकि तालिबान भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत की मुख्य चिंता यह है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तालिबान कई बार भारत सरकार को यह आश्वासन दे चुका है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देगा। कुछ महीने पहले भारत के विदेश सचिव ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी।

कासगंज में प्रशासन अलर्ट — डीएम प्रणय सिंह और एसपी अंकिता शर्मा ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

कासगंज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली एवं परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का गहराई से जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम को चेक किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा समाप्ति के बाद बस स्टैंड और

रेलवे स्टेशन पर भी आवश्यक सतर्कता और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की सक्रियता से परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न कराने की पूरी तैयारियां पूरी की गईं।

आखिर गठबंधन की 'गदहपचीसी' में कबतक उलझा रहेगा बिहार ? बताएं नेता-मतदातागण !

कमलेश पाण्डेय

सिद्धांत विहीन गठबंधन की राजनीति से किसी भी जीवंत लोकतंत्र का कदापि भला नहीं हो सकता है। बिहार इसका दिलचस्प उदाहरण बन चुका है। यहां पर नीति और नियम दोनों का मखौल उड़ाया जा रहा है। चाहे एनडीए हो या इंडिया महागठबंधन (पूर्व नाम यूपीए), दोनों जगहों पर टिकट बंटवारे में जितनी सिरफुटौव्वल दिखाई पड़ी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि मतदाताओं ने समझदारी नहीं दिखाई तो 14 नवम्बर से सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होना तय है।

सच कहूं तो इस फजीहत भरी सियासी स्थिति के लिए भाजपा और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उनके बीच बारहों मास चलते रहने वाले शह और मात के अनैतिक खेल से उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के इकबाल बुलंद रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्रीद्वय लालू यादव व राबड़ी देवी) तो महज इनके हथकंडे मात्र हैं।

लेकिन कभी एक-दूसरे की सियासी उन्नति की सहायक रहे नीतीश कुमार और लालू यादव इतने सजग रहते हैं कि इन्होंने एक-दूसरे का प्रबल विरोधी रहने के बावजूद दो-दो बार आपस में हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इन्होंने भाजपा-कांग्रेस की सियासी तिकड़मों को बिहार में कभी सफल नहीं होने दिया। खास बात यह कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के टिकट बंटवारे से पहले भी इन्होंने यानी जदयू ने भाजपा को और राजद ने कांग्रेस को, उनके गठबंधन सहयोगियों को उकसाकर जो गुप्त सियासी खेल खेला है, उससे राजनीतिक विश्लेषकों का भी दंग रह जाना स्वाभाविक है।

जदयू का यह कहना कि लोजपा आर, हम और रालोमो को भाजपा मैनेज करे, यह एक गहरी सियासी चाल है. वहीं तेजस्वी यादव के परोक्ष इशारे पर वीवीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा कांग्रेस पर तंज कसना और कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें ऑफर करना, साथ ही भाकपा माले द्वारा अधिक सीटों की मांग करना यह जाहिर करता है कि राजद अपने सहयोगियों को सीट बंटवारे के दौरान इतना कमजोर रखना चाहता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी इनकी मोलभाव की ताकत कम रहे। यही पेंच जदयू की भी है लेकिन भाजपा ने उसे 122 से 101 तक झुकाकर अपनी बढ़त बना ली है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि गठबंधन की बुनियाद पर लड़े जा रहे चुनाव में पहली और बड़ी चुनौती यही रहती है कि गठबंधन के भीतर किस तरह से सहयोगी दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बिठाया जाए यानी कि सही संतुलन साधा जाए। इस नजरिए से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सहयोगियों के बीच सीटों की संख्या के बंटवारे की गुत्थी पहले ही सुलझाकर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है लेकिन सीटों के बंटवारे का असली पेंच यहां भी खबर लिखे जाने तक फंसा हुआ है।

सियासी टिप्पणीकारों की मानें तो बिहार में राजग या महागठबंधन के 2020 के मुकाबले 2025 में गठबंधनों के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी समीकरण बदल चुके हैं, जिसका तीखा असर सीट शेयरिंग पर भी दिख रहा है। एनडीए में जदयू और बीजेपी बराबर-बराबर सीटों पर मैदान में हैं जबकि बाकी दलों को उनकी मांग से काफी कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जिससे वे लोग बाहर से खुश और अंदर से नाखुश हैं। उनकी सियासी कविताएं इसी बात की चुगली करती हैं। हालांकि गठबंधन के लिए अच्छी बात यह होगी कि किसी सहयोगी दल ने खुलेआम नाखुशी जाहिर नहीं की है, क्योंकि अब में निर्विकल्प हो चुके हैं।

जानकारों की मानें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां लेकर आया है।

गड़बड़झाला..... ध्यान दो सरदार : स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

अब तो पूरे देश में उत्सव की ज्योति प्रकाशमान होने वाली है। त्योहार व पर्व की मस्ती में नए जमाने के सुकून के पल नहीं, भागम-भाग की दौड़ है। इसलिए रेडिमेड का दौर है, सब चीजें बनी- बनाई चहिए सभी को। बुजुर्ग वर यह तमाशा देख कर मुस्काते हैं और कहते हैं "वाह रे नया जमाना।" शुद्धता के लिए परेशान लोग, नकली हवा व कृत्रिम साँसो के लिए भी भाग-दौड़ अब पहचान ही कहाँ है ? सब जगह अपनी-अपनी डफली अपना ढोल बजा रहा है हर कोई, लेकिन कुछ ऐसे लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं लोगों को चूना लगाने की और नम्बर २ का खेल खेलते हैं। कभी मिलावट पर भी ध्यान दो सरदार। बहुत परेशानी है, शुद्धता की चाह में हम तो दर-दर भटक रहे हैं। गांव - शहर में हम तो जीते-जी मर रहे हैं। अब आप फिर से आओ हमारे यहाँ असरदार बन कर। झिलमिलाती इस रोशनी में काली छाया यानी काला कारोबार इतना ज्यादा हो रहा है कि हमें तो समझ में नहीं आता है। जांच-पड़ताल के नाम पर कारोबारी झोली भर देते हैं, दाता फिर कौन-सी रिपोर्ट या जांच? सबके-सब बेकार साबित हो रहे हैं। हवन-पूजन धूप-दीप को भी नहीं छोड़ते, चोट पर चोट करते हैं। शुद्ध देसी घी अपनी असली पहचान को तलाश रहा है। सौ प्रतिशत शुद्ध घी मिलना मुश्किल है, और दूध में मिलावटी क्या-क्या मिला रहे हैं, अगर देख लेंगे तो आंखें चार हो जाएगी। पनीर भी रसायन युक्त नकली और मावा तो हर वर्ष अपना नाम रोशन कर रहा है 'नकली मावा' नाम से। फिर क्या करें, मुनाफाखोरों ने हमारी खाने-पीने की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा। इन्हें तो सिर्फ पैसे कमाने की चिंता है, जो लोगों के लिए चिता साबित होती है। अभी नकली दवाई की बात है, और कहीं ऊँची दुकान और फीके पकवान की बात है। परम्परागत बाजारों की रौनक तो अब मॉल व शो-रूम ने ले ली है। उपभोक्ताओं को सब ठगा हुआ लग रहा है, फिर भी आदमी नए जमाने में भेंड़चाल चलने को मजबूर है, लेकिन रेडिमेड में विश्वास करने वाली नई पीढ़ी जेन जी यानी नए जमाने को सब तैयार और हाथों-हाथ चहिए। उसे इंतजार करना पसंद नहीं है। कम्प्यूटर, लेपटॉप और मोबाइल के युग में बड़ी-बड़ी बातों में उलझ जाते हैं, पर बाद में कर व अलग-अलग प्रभार में घिरते हुए उपभोक्ता व्यापारियों के जाल में फंस जाते हैं। बाद में पछताता भी है, लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत।

त्योहारों के मौसम में यह सब गड़बड़झाले का खेल ज्यादा तेजी से खेला जाता है। मिलावटी वस्तुओं ने पूरे तंत्र को अपने मोहपाश में घेर लिया है। और सरदार तो मस्त ही नहीं, वह तो कुछ देखते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, और कुछ सुनते ही नहीं हैं। यानी वह देखते तो सब कुछ हैं लेकिन मौन हैं, जो खतरनाक साबित हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों के इस वन-डे, टेस्ट या टी-ट्वेंटी मैच में कोच असरदार चाहिए, तभी परिणाम में अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो मिलावट के सौदागरों की जमात और बढ़ती जाएगी, जिससे लोगों को भी तकलीफ़ होगी। इसलिए कहता हूँ इस और ध्यान दो सरदार।

विश्व छात्र दिवस,डॉ. कलाम का पूरा जीवन एक जीवंत प्रेरणा है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

हर साल 15 अक्तूबर को जब विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, तो यह दिन हमें केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें यह एहसास भी कराता है कि किसी मुल्क की असल ताक़त उसकी युवाशक्ति में छिपी होती है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि दुनिया भर के विद्यार्थी यह समझें कि वे एक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं और उन्हें उस वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि का अनुसरण करना चाहिए, जिसे डॉ. कलाम ने अपने जीवन से परिभाषित किया।डॉ. कलाम का पूरा जीवन एक जीवंत प्रेरणा है। रामेश्वरम के एक साधारण मछुआरे परिवार से निकल कर भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा विज्ञान की बुलंदियों तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अगर ईमानदारी, परिश्रम और लगन से काम करे तो कोई मंज़िल दूर नहीं। वह केवल मिसाइल मैन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शिक्षक थे जिनकी हर बात में विद्यार्थियों के प्रति स्नेह, विश्वास और उम्मीद झलकती थी। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों में असीम ऊर्जा है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है।आज जब शिक्षा प्रतिस्पर्धा और रोज़गार की दौड़ तक सीमित होती जा रही है, तब कलाम साहब की विचारधारा और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने सदैव कहा कि शिक्षा का मक़सद नम्बर या डिग्री नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने की सोच होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि "इग्नाइटेड माइंड्स" अर्थात जगाई हुई चेतनाएँ,किसी भी राष्ट्र की असली पूँजी हैं। यही कारण था कि वे हर छात्र को अपने भीतर का सपना पहचानने और उसे साकार करने का साहस देते थे।विश्व छात्र दिवस केवल उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का दिन भी है। आज के युवाओं के सामने जहाँ तकनीक और अवसरों के असीम आयाम हैं, वहीं वे जलवायु संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक विषमता जैसे प्रश्नों से जूझ रहे हैं। ऐसे में डॉ. कलाम का यह संदेश दिशा देता है, ज्ञान को करुणा के साथ जोड़ना सीखो, क्योंकि केवल जानकारी से नहीं, बल्कि संवेदना से समाज बदलता है।इस अवसर पर हर संस्थान और हर विद्यार्थी को यह प्रण लेना चाहिए कि वे डॉ. कलाम के आदर्शों को अपने आचरण में उतारेंगे शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाएँगे, और सपनों को कर्म का रूप देंगे। जब ऐसा होगा, तब सचमुच यह दिवस मानवता और प्रगति का पर्व बनेगा। डॉ. कलाम के शब्दों में कहें तो "एक पुस्तक, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं।" यही वाक्य आज भी हर दिल में उम्मीद की लौ बनकर जगमगा रहा है, और हमें याद दिला रहा है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण कक्षा से ही आरंभ होता है।

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: पुराने घोटालों की जड़ें, डॉक्टरों का फार्मा गठजोड़ और सरकार की नाकामी का काला अध्याय

परिवहन विशेष न्यूज

कटनी। छिंदवाड़ा के कफ सिरप कांड ने न सिर्फ 25 मासूम बच्चों की जान ले ली, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्रीसन फार्मा की 'कोलड्रिफ' सिरप से हुई मौतों ने पुराने दम तोड़ चुके घोटालों को फिर से उजागर कर दिया है—जिनकी जड़ें 2015 तक जाती हैं। लेकिन सरकार की नकारात्मक नीतियां और डॉक्टरों का फार्मा कंपनियों से गहरा गठजोड़ इस त्रासदी का असली विलेन है। कटनी के डॉ. प्रवीण वैश्य समेत प्रदेश के अन्य 20 डॉक्टरों पर नोटिस जारी होने के बाद भी सवाल वही है: क्या यह सिर्फ दिखावा है, या सिस्टम की सड़ांध को साफ करने की दिशा में कोई कदम ? उत्तर सबको मालूम है शासन अपनी कटी नाक की मरहम पट्टी करने का अभियान शुरू कर रहा है, जनता को भृमित करने के लिए नॉन एलोपैथिक डाक्टर्स को झोलाछाप बताकर उनकी गर्दन दबोचने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्योंकि बीमार व्यवस्था में यही कथित झोलाछाप चिकित्सक और पैथो -टेक्निशियन सबसे कमजोर वर्ग है जिन्होंने कोविड में सस्ता ईलाज किया और निडरता से किया , मानवीयता दिखाई, शासन ने तत्समय सराहा भी बाद में उन्हें उपेक्षित कर दिया , प्रताड़ति करके रख दिया और मौज से जन धन को लूटने वाले , सैर सपाटा करने वाले मंहगा ईलाज देने वाले मान्य डाक्टर्स हमेशा की तरह बचाए जाएंगे।

10 साल पुराना काला खेल: दबाई गई शिकायतें, भूले वादे

यह कांड नया नहीं है। 28 अगस्त 2015 को रायपुर के व्हिसलब्लोअर विकास तिवारी ने एक साहसी शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने खुलासा किया था कि डॉक्टर फार्मा कंपनियों से विदेश यात्राओं का लालच लेकर उनकी दवाएं बेमुरौवत लिख रहे हैं। यूएसवी लिमिटेड ने 2014 में डॉक्टरों और उनके परिवारों को इटली की सपरिवार यात्रा पर भेजा था, जहां कंपनी ने खर्च उठाया। लेकिन यह शिकायत 10 साल तक फाइलों में दफन रही। अब, 30 सितंबर 2025 को अचानक 20 डॉक्टरों को नोटिस—क्या यह संयोग है या चुनावी ड्रामा ? स्थानीय सूत्र बताते हैं कि यह गठजोड़ तब से चल रहा है, जब 2015 में ही मध्य प्रदेश में फार्मा-डॉक्टर नेटवर्क ने जड़ें जमा ली थीं।

वर्तमान में, छिंदवाड़ा कांड ने इस पुरानी बीमारी को फिर से जगा दिया। श्रीसन फार्मा की 'कोलड्रिफ' सिरप में 48.6% डायइथाइलीन ग्लाइकॉल में एक जहरीला रसायन मिला था, जो किडनी फेलियर का सबब बना। 20 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, और 5 अभी भी जिंदगी से जूझ रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है।

सिर्फ एक डॉक्टर पर नोटिस, सरासर अन्याय है

कटनी के डॉ. प्रवीण वैश्य पर नोटिस क्यों ? स्थानीय स्तर पर 80% डॉक्टर फार्मा कंपनियों से जुड़े हैं—कमीशन, गिफ्ट्स और विदेशी टूर के बदले वे कंपनियों की दवाएं प्राथमिकता से लिखते हैं। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कटनी का नेटवर्क इतना गहरा है कि निष्पक्ष जांच हुई तो दर्जनों नाम उजागर हो जाएंगे। लेकिन सरकार की नीतियां इतनी ढीली हैं कि ये घोटाले बार-बार दोहराए जाते हैं।"

वर्तमान की कड़वी सच्चाई: डॉक्टरों पर गाज, लेकिन सिस्टम बेदाग ?

आजकल पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने 20 डॉक्टरों को नोटिस थमाए हैं, जिनमें कटनी के डॉ. वैश्य का नाम प्रमुख है। लेकिन यह कार्रवाई कितनी गंभीर ? डॉ. वैश्य जैसे चिकित्सक, जो सालों से स्थानीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं, फार्मा एजेंट्स से नियमित गिफ्ट्स और टूर ऑफर लेते रहे। बदले में, मरीजों को कंपनी की दवाएं थोपी जाती हैं—चाहे वे जरूरी हों या न हों। छिंदवाड़ा में डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी इसका उदाहरण है, जिन्होंने सिरप लिखा और बच्चे मर गए। लेकिन असली सवाल डॉक्टरों पर ही क्यों ? फार्मा कंपनियां बिना डॉक्टरों के समर्थन के इतना बड़ा खेल कैसे खेलतीं ?

असली दोषी हैं -सरकार की नीतियाँ

सरकार की नकारात्मक नीतियां इसकी जड़ हैं। दवा नियंत्रण विभाग की लापरवाही ऐसी कि श्रीसन फार्मा को 364 उल्लंघन के बावजूद लाइसेंस मिला रहा। तमिलनाडु में फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो 300 से ज्यादा गंभीर कमियां मिलीं—फिर भी बिक्री जारी रही। मध्य प्रदेश में दवा निरीक्षण की व्यवस्था नाममात्र की है; इंस्पेक्टरों की भर्ती रुकी हुई है, और पुरानी शिकायतें दबाई जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि भारत के कफ सिरप स्कैंडल वैश्विक खतरा है। 2023 में गैम्बिया में भारतीय सिरप से 70 बच्चे मरे थे। लेकिन हमारी सरकार ? सिर्फ बैन और नोटिस—कोई ठोस सुधार नहीं।

भविष्य की आशंकाएं: और कितने बच्चे होंगे बलि ?

अगर वर्तमान की कार्रवाई को ही भविष्य का आईना मानें, तो डर लगता है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि पूरे प्रदेश में जांच होगी, लेकिन इतिहास गवाह है—2015 की शिकायत दब गई, 2023 के स्कैंडल भूले गए। डॉक्टरों पर मेडिकल काउंसिल से कार्रवाई और आपराधिक मुकदमे की धमकी है, लेकिन फार्मा नेटवर्क की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि बिना सख्त कानून के कुछ नहीं बचेगा। कटनी जैसे छोटे शहरों में 80% डॉक्टर प्रभावित हैं—अगर निष्पक्ष जांच हुई तो स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी। लेकिन सरकार की नीतियां नकारात्मक ही रहेंगी: बजट कटौती, निरीक्षण में ढिलाई, और भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदना। जनता का गुस्सा सही है—क्या ये नोटिस दिखावे के लिए हैं, या सिस्टम क्लीन होगा ?

एक मां, जिसका बच्चा 'कोलड्रिफ' से मरा, कहती हैं, "डॉक्टरों ने दवा लिखी, कंपनी ने जहर बेचा, और सरकार ने सोया। अब नोटिस से क्या फर्क ?₹ सवाल वही है—क्या डॉक्टरों का यह गठजोड़ टूटेगा, या भविष्य में और मासूमों की बलि चढ़ेगी ? समय सरकार को जवाब देने का है, वरना यह काला अध्याय इतिहास दोहराएगा।

सीएम योगी के दरबार में पहुंचा 1250 रुपए की वसूली का केस, आरोपी को फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने पकड़ा

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के पनकी बॉटलिंग प्लांट में चल रहे अवैध वसूली के रैकेट का खुलासा किया है। यहां पर हर सिलेंडर लदे ट्रक से 1250 रुपये की जबरन उगाही करने वाले सिंडीकेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली शिकायत के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और पूछताछ में सिंडीकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया। मामले में विभागीय अधिकारियों की मिली भगत की भी आशंका जताई जा रही है।

घटना की शुरुआत कानपुर के दबौली वेस्ट संत कबीर नगर निवासी ट्रक चालक संतोष कुमार की शिकायत से हुई। संतोष का ट्रक आईओसी के बॉटलिंग प्लांट से अटैच है। यहां से निकलने वाले हर ट्रक से प्रति चक्कर 1250 रुपये की वसूली की जा रही थी। संतोष ने स्थानीय पनकी थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार, 4 अक्टूबर को वह सीएम योगी की जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। सीएम योगी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच के आदेश दिए।

ऐसे खुली पोल सीएम ऑफिस के निर्देश पर एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने मामले में कार्रवाई की, उन्होंने दो पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में संतोष के ट्रक में बैठाया। ट्रक के प्लांट से निकलते ही वसूली करने वाले को 1250 रुपये देते हुए पकड़ लिया गया। आरोपी ने अपना नाम राजस्थान के भरतपुर निवासी मोहन बताया, जो प्लांट में मुंशी के तौर पर काम करता है। उसके पास से 1200 रुपये की घूस बरामद हुई। पूछताछ में मोहन ने कबूल किया कि पैसे वह नहीं लेता, बल्कि कंपनी का ठेकेदार किशनलाल गोयल लेता हैं, उसने भगवान की कसम खाते हुए कहा, 'साहब, यह पैसे मैं नहीं लेता'।

पुलिस ने आरोपियो को पकड़ा मोहन की निशानदेही पर पुलिस ने कानपुर देहात के गजनेर निवासी सुमेंद्र भदौरिया और किशनलाल गोयल को हिरासत में लिया। सोमवार देर रात तक तीनों से पूछताछ चली। पनकी थाने में संतोष की तहरीर पर मानेंद्र भटनागर, संतोष कुमार, किशनलाल गोयल, सुमेंद्र भदौरिया और मोहन के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।

डीसीपी ने क्या कहा ? डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया, 'आईओसी के सिलेंडर डिपो में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का सिंडीकेट चल रहा था। पुलिस ने मामले को उजागर कर एफआईआर दर्ज की है। जांच में विभाग के कुछ लोगों की मिलीभगत सामने आ रही हैऔर जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने अब पूरे सिंडीकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए छानबीन तेज कर दी है।

इंफोसिस में स्लाइट के 82 छात्रों का चयन संस्थान की शानदार उपलब्धि : निदेशक प्रो.मणिकांत पासवान

लोंगोवाल,14 अक्टूबर (जगसीर सिंह)-

संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (स्लाइट), लोंगोवाल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि हाल ही में आयोजित कैंपस भर्ती अभियान में इंफोसिस ने संस्थान के 82 छात्रों का चयन किया है ।अपनी खुशी व्यक्त करते हुए स्लाइट के निदेशक प्रो. मणिकांत पासवान ने कहा,

"मुझे यह शानदार उपलब्धि साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह सफलता हमारे छात्रों की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत, हमारे संकाय के समर्पित प्रयासों, और संस्थान द्वारा उद्योग के साथ स्थापित मजबूत अकादमिक-औद्योगिक सहयोग का परिणाम है ।₹प्रो. पासवान ने सभी चयनित छात्रों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके परिश्रम और प्रतिभा से संस्थान को गौरवान्वित करने के लिए सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल की लगातार सहयोग और उत्कृष्ट समन्वय के लिए भी प्रशंसा की, जिसने इस तरह के उत्कृष्ट प्लेसमेंट अवसर प्रदान करने में मदद की ।उन्होंने आगे कहा, ₹यह सफलता उनके करियर में कई उपलब्धियों में पहली हो,मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूँ कि वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रयासरत रहें और जहाँ भी जाएँ, स्लाइट के मूल्यों को बनाए रखें, ₹यह उपलब्धि पंजाब में तकनीकी शिक्षा और उद्योग-उपयुक्त प्रतिभा के लिए स्लाइट की बढ़ती पहचान को दर्शाती है।

जीएसटी कमिश्नर से मिले केमिस्ट एसोसिएशन प्रतिनिधि

"हर समस्या का हल हमारी प्राथमिकता, उपभोक्ता को राहत सबसे पहले" – जतिंदर जोरवाल

संगरूर,14 अक्टूबर (जगसीर लोगोंवाल)-

पंजाब के जीएसटी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल (आईएएस) से केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर जीएसटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। बैठक का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नरेश जिंदल ने किया।

इस दौरान नई जीएसटी दरों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और केमिस्ट समुदाय के कई भ्रम दूर किए गए। कमिश्नर जोरवाल ने स्पष्ट किया कि नई दरें लागू होने के बाद दवाओं समेत कई ज़रूरी वस्तुओं के दाम कम हुए हैं, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह तत्पर है और हर शिकायत का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जोरवाल ने कहा — "हमारा उद्देश्य दोहरा है — उपभोक्ता को राहत देना और कारोबारी की परेशानी दूर करना। विभाग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है।"

जिला अध्यक्ष नरेश जिंदल ने कहा कि केमिस्ट एसोसिएशन सरकार और विभाग के बीच सेतु का कार्य करेगी ताकि जमीनी स्तर तक राहत पहुंच सके। इस मौके पर संगरूर एसोसिएशन की ओर से कमिश्नर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया ।

हरे माधव वर्सी पर्व 2025- आस्था की धरा पर अवतरित दिव्यता का अनुभव-अमृत वर्षा क़ा आभास

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर आध्यात्मिकता रूपी मिठास मेंडूबे भारत के मध्यप्रदेश की पावन धरा कटनी की शांत और पावन भूमि पर 9 और 10 अक्टूबर 2025 को ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसे शब्दों में बाँध पाना अपने आप में एक आध्यात्मिक साधना के समान है। हरे माधव सत्संग के वर्सी महोत्सव ने न केवल शहर बल्कि देश और विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को एक सूत्र में पिरो दिया ।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र व मेरे साथी मनोहर सुगानी सतना ने वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हमें इस दौरान श्रद्धा,सेवा,भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। हमने स्वयंम इन दो दिवसीय सत्संग के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग की,और यह अनुभव किसी साधारण धार्मिकआयोजन से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक क्रांति जैसा था।

साथियों बात अगर हम भक्तों के अभूतपूर्व उत्साह की करें तो, हरे माधव दयाल,जिनकी करुणा और दया की गाथाएँ भक्तों के मुख से सहज ही फूट पड़ती हैं, उनके नाम का प्रभाव इस आयोजन में स्पष्ट रूप से झलकता दिखा ।हर ओर "हरे माधव" का उच्चारण मानो वातावरण को पवित्र कर रहा था। भक्तों की आँखों में जो चमक थी, वह किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि अंतर्मन में अनुभव की गई शांति और दयालुता की झिलमिल थी ।इस सत्संग ने यह सिद्ध कर दियाकिआध्यात्मिकता तब ही सशक्त होती है जब उसमें मानवता की सुगंध हो ।कटनी की इस पवित्र भूमि पर जैसे ही 9 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय हुआ, हरे माधव दयाल के प्रति भक्ति की तरंगें पूरे शहर में फैल गईं, मानों बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग और युवा सबकी एक ही चाह थी,₹दयाल के दर्शन और सत्संग का श्रवण ।₹ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर ही भक्ति में रमा हुआ है ।यह दृश्य केवल आँखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था।

साथियों बात अगर हम देश- विदेश से उमड़ा श्रद्धा का सागर, वैश्विक स्तरपर आध्यात्मिक एकता की करें तो इस वर्सी महोत्सव की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि इसमें भारत के अनेक राज्यों से अनुमानतः हजारों लाखों भक्तों ने इस दो दिवसीय सत्संग का लाभउठाया। भक्तों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि हरे माधव दयाल की शिक्षाएँ सीमाओं से परे जाकर मानवता को जोड़ रही हैं ।जब मैंने ग्राउंड पर भक्तों से बात की, तो उन्होंने कहा"हम यहाँ किसी धर्म के अनुयायी बनकर नहीं, बल्कि प्रेम और शांति की तलाश में आए हैं। यहाँ जो अनुभव मिलता है, वह किसी भी किताब में नहीं।"इससे यह सिद्ध हुआ कि आज के वैश्विक युग में भी सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो सभी जाति,भाषा और सीमाओं को मिटाकर मनुष्यता के सूत्र में जोड़ती है।

साथियों बात अगर हम सत्संग के पहले दिन 9 अक्टूबर 2025 अमृत वर्षा क़े प्रारंभ होने की करें तोपहले दिन का आरंभ मंगल वंदना और " मेरे सतगुरां हम शरण तेरी आए " के भक्ति स्वर से हुआ। वातावरण में घुली शांति,भजन के मधुर सुर और आरती की लौ ने ऐसा माहौल रचा कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसी क्षण स्थिर हो गया हो ।मैंने मोबाइल कैमरे की लेंस से जब भक्तों के चेहरों को कैद किया, तो हर चेहरे पर संतोष, श्रद्धा और आनंद की अनोखी अभिव्यक्ति थी। पहले दिन का मुख्य आकर्षण बाबा ईश्वर शाह साहिब जी का"दयाल संदेश"यानें अमृत वर्षा था,जिसमें कलश करुणा, क्षमा और आत्मचिंतन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सत्संग पंडाल में गूँजती मधुर वाणी ने हजारों मनों को छू लिया। ऐसा लगा मानो हृदय के भीतर छिपी सभी थकान, चिंता और अशांति उसी क्षण विलीन हो गई हो।

साथियों बात अगर हम सत्संग के दूसरे व अंतिम दिन 10 अक्टूबर 2025 की करें तो मानो आकाश से उतरती दिव्यता पृथ्वी को नमन कर रही हो,सुबह 10 बजे से ही भक्तों का सत्संग स्थल पर पहुंचना शुरू गया था,यह सामूहिक श्रद्धा और अनुशासन का अनुपम उदाहरण था। बच्चे अपने हाथों में फूल और झंडे लिए, युवा सेवा में तत्पर, बुजुर्गों के चेहरे पर आत्मिक आनंद। यह सब देखकर लगा कि जब आस्था और अनुशासन एक साथ चलें तो समाज में कितनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है ।बाबाजी का आगमन विशाल जुलूस के साथ हुआ एलईडी स्क्रीन पर बाबा माधव शाह बाबा नारायण शाह की अनेक महिमाओं लीलाओं का वर्णन साक्षात रूप से भक्तों को दिखाया गया जिससे भक्तों के अनेक प्रश्नों की जिज्ञासा दूर हुई उसके पश्चात बाबा जी ने स्वयं अपने मुख से सत्संग की अमृत वर्षा की जिससे भक्तजन भाव विभोर हो उठे।

साथियों बात अगर हम सेवा के विविध रूप,व्यवस्थापन का अनुकरणीय उदाहरण की करें तो,यह मेरे लिए इस आयोजन का सबसे प्रेरणादायक पहलू था,इसकी उत्कृष्ट सेवा व्यवस्था। सत्संग परिसर में व्यवस्थापकों और स्वयंसेवकों ने जिस निष्ठा से सेवा दी, वह अपने आप में उदाहरण है, जिसकी मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर मोबाइल कैमरे में सेव किया ।पंडाल सेवा-विशाल पंडालों में बैठने, धूप से बचाव, वेंटिलेशन, और व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि अनुमानतः हजारो लाखों की भीड़ होने के बावजूद कोई अव्यवस्था नहीं दिखी ।चरण पादुका सेवा-श्रद्धालुओं के लिए चरण पादुका स्थल पर विनम्र भाव से सेवा करते स्वयंसेवक विनम्रता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहे थे ।जल सेवा-ठंडा,शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए अनेक जल स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ लगातार सेवा चल रही थी ।खोया-पाया सेवाः इतने बड़े आयोजन में कोई वस्तु खो जाए,तो तुरंत सूचना मिल जाए,भंडारा यानी लंगर सेवा तथा बर्तन थालियां धोने की सेवा में मैंने देखा कि बड़े-बड़े अमीरों उच्च स्तरीय लोग, भक्तों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की थालियों को मांझकर फ़रि पानी में फिर धो रहे थे जो मुझे सबसे अनमोल सेवा लगी उनकी यह सेवा रेखांकित करने योग्य है ।पुलिस विभाग और सुरक्षा व्यवस्था-कटनी पुलिस और सुरक्षा दल ने अनुकरणीय कार्य किया। भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया ।मेडिकल सेवा-24 घंटे संचालित मेडिकल कैंप में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हर समय मौजूद रहे। किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था भी तत्पर थी ।स्टालों में एक झाड़ माँ के नाम,पर्यावरणीय पहल- इस आयोजन की विशेषता रही "एक झाड़ माँ के नाम" पहल, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भक्त ने एक पौधा रोपने का संकल्प लिया। आध्यात्मिकता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का यह संदेश अत्यंत प्रेरणादायक था। विशेष रूप से व्यवस्थापकों सेवादारियों की सेवाएं अभूतपूर्व अनुशासन के रूप में दिखाई दी सत्संग स्थल के बाजू में हेड ऑफिस बनी हुई थी जहां से व्यवस्थापकों की हर सेवा पर नजर थी ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो,इन सभी व्यवस्थाओं को देखकर लगा कि जब सेवा भावना और संगठन शक्ति साथ मिलती है,तो कोई भी आयोजनकितना अनुशासितऔर प्रेरणादायक बन सकता है।

साथियों बात अगर हम व्यवस्था में अनुशासन और तकनीक का सुंदर संगम की करें तो,मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने पाया कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यवस्थापन का भी उत्कृष्ट उदाहरण था ।आयोजकों ने आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया था, सीसीटीवी निगरानी,एलईडी लाइव प्रसारण ताकि दूर बैठे भक्तों को भी स्पष्ट नजर आए,जैसी सुविधाएँ मौजूद थीं। इससे यह महोत्सव केवल एक भौतिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि डिजिटल आध्यात्मिकता का भी एक युगीन उदाहरण बन गया।

साथियों बात अगर हम भक्तों के भाव,अनुभवों की झंकार की करें तो,जब मैंने कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की, तो हर किसी की आवाज़ में भक्ति और भावनाओं की गहराई झलक रही थी ।दमोह निवासी एक महिला ने कहा,"हम हर वर्ष आते हैं, लेकिन इस बार जो दिव्यता और शांति महसूस हुई, वह पहले कभी नहीं हुई। यह सचमुच अमृत वर्षा थी।"कोल्हापुर से आए एक युवा भक्त ने कहा,"मैं तकनीकी क्षेत्र से हूँ, पर यहाँ आकर समझा कि असली 'कनेक्शन'ईश्वर से जुड़ाव है, न कि इंटरनेट से।"इन सरल वाक्यों में वह आध्यात्मिक सत्य छिपा है जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देता है ।आध्यात्मिकता और समाजसेवा का संगम-हरे माधव सत्संग केवल उपदेश देने वाला मंच नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत सामाजिक आंदोलन भी है। इस महोत्सव के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक जनसेवा अभियानों कि हमें प्रेरणा मिली ।हरे माधव परमार्थ सेवा समिति कटनी द्वारा गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा बाबा माधव शाह चिकित्सालय मासिक अनाज वितरण साहित्य अनेकयोजनाओं का संचालन किया जाता है ।यह देखकर लगा कि सच्ची भक्ति वही है जो समाज में परिवर्तन का माध्यम बने। आध्यात्मिकता तभी सार्थक है जब वह मानवता के कार्यों में उतरकर समाज को उन्नति की दिशा में ले जाए।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से हरेमाधव सत्संग की प्रासंगिकता को समझने की करें तो,विश्व स्तर पर आज जब तनाव, हिंसा, युद्ध और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, तब हरे माधव दयाल का संदेश, "दयालता ही मानवता का आधार है"अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है। कटनी का यह आयोजन केवल धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि"वसुधैव कुटुंबकम्" के भारतीय आदर्श का जीवंत प्रमाण था ।कोल्हापुर मुंबई सहित अनेक मेट्रो सिटी से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें यहाँ वह "मेडिटेशनल एनर्जी" मिली जो किसी भी मानसिकचिकित्सा से अधिक प्रभावशाली है।

साथियों बात अगर हम मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो, मुझे इसके लिए संस्था या व्यवस्थापकों नें कहा नहीं था, gullमैंने स्वतः संज्ञान से ग्राउंड रिपोर्टर की आत्मानुभूति,शब्दों से परे एक साक्षात्कार-जब मैंने इन दो दिनों की रिपोर्टिंग पूरी की,तो महसूस किया कि वकालत क़े पेशे जैसे केवल तथ्य नहीं, बल्कि अनुभूति का भी माध्यम है। कैमरे में कैद दृश्य भले सीमित हों, पर हृदय में जो दृश्य अंकित हुए, वे जीवनभर अमिट रहेंगे ।मैंने देखा कि किस प्रकार भक्त भक्ति में डूबकर सेवा करते हैं, किस तरह व्यवस्थापक दिन-रात बिना थके अपने कर्तव्यों में लगे रहे,और कैसे एक संत का सन्देश लाखों के जीवन में प्रकाश बन जाता है ।यह रिपोर्ट केवल रिपोर्ट नहीं, एक साक्षात्कार है,आत्मा का, श्रद्धा का,और मानवता का।

समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव का तीन दिवसीय दौरा

परिवहन विशेष न्यूज

बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सांसद मा. आदित्य यादव 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बहजोई (जनपद सम्भल) में आयोजित भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशा समिति की बैठक में होंगे शामिल।

इसके बाद गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक एवं निजी कार्यक्रमों में लेंगे भाग।

रात्रि विश्राम यारा फर्टिलाइजर, बबराला (सम्भल) में करेंगे।

15 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन, बबराला में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनता से करेंगे मुलाकात।

दिनभर बदायूं लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रात्रि विश्राम डीएम रोड, सिविल लाइंस, बदायूं स्थित निज निवास पर करेंगे। 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से निज निवास, बदायूं में कार्यकर्ताओं और आम जनता से करेंगे भेंट एवं उनकी समस्याएं सुनेंगे।

तत्पश्चात क्षेत्र के राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में रहेंगे सहभागी। तीन दिनों तक सांसद आदित्य यादव का दौरा रहेगा बेहद व्यस्त और जनसंपर्क से भरपूर।

भिवाड़ी पुलिस का बड़ा साइबर ऑपरेशन: 183 मामलों में 122 करोड़ की ठगी का खुलासा, दिल्ली से गिरफ़्तार 'खाता सौदागर

रिपोर्ट अंकित गुप्ता दिल्ली

भिवाड़ी पुलिस का बड़ा साइबर ऑपरेशन: 183 मामलों में 122 करोड़ की ठगी का खुलासा, दिल्ली से गिरफ़्तार 'खाता सौदागर'!

जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में भिवाड़ी की साइबर क्राइम थाना टीम ने एक ऐसी सनसनीखेज कार्रवाई की है जिसने पूरे देश के साइबर ठग नेटवर्क को हिला दिया है। पुलिस ने विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों के बैंक खाते कमीशन पर साइबर ठगों को बेचने वाले आरोपी अंकित शर्मा (33), निवासी बागपत, उत्तर प्रदेश (वर्तमान में वेस्ट कान्ती नगर, दिल्ली) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी के कब्जे से 38 बैंक खातों की चेक बुक, 4 पासबुक, 20 एटीएम कार्ड, 8 क्यूआर कोड, 1 स्वाइप मशीन, 9 मोबाइल फोन, 9 रबर मोहर, एक इंकपैड, तथा 2.50 लाख नगद बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इन खातों का उपयोग देशभर के विभिन्न राज्यों में 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 183 साइबर ठगी शिकायतों में किया गया था, जिनसे अब तक 122 करोड़ 21 लाख 59 हजार 57 रुपये की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है।

इससे पहले इसी नेटवर्क से जुड़े दो आरोपी राशिद और अजमत को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 11 चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, 1 स्वाइप मशीन, 5 मोबाइल बरामद हुए थे। इनके खातों से जुड़े 96 मामलों में 61 करोड़ की ठगी दर्ज पाई गई थी।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, अति. पुलिस अधीक्षक अतुल साहू और वृताधिकारी जयसिंह आरपीएस के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। इस पूरे अभियान में कांस्टेबल आशीष, संदीप, मुकेश, रजत शर्मा और मंजीत की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। भिवाड़ी साइबर पुलिस की इस सटीक और त्वरित कार्रवाई ने न सिर्फ करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़ किया है, बल्कि यह भी उजागर किया है कि "म्यूल अकाउंट" बेचने वाले लोग अब खुद अपराधी माफिया के हिस्से बन चुके हैं। यह ऑपरेशन राजस्थान पुलिस की साइबर सेल की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे सफल कार्यवाही मानी जा रही है।

(समाज सेवा विशेष) "कुर्सी नहीं, भरोसे की राजनीति: रमेश वर्मा का सफ़र"

(स्वयं विधायक पद का चुनाव नहीं लड़ा, पर कई विधायकों की डूबती नैया पार लगवाई।) भिवानी के गाँव बड़वा में जन्में रमेश वर्मा की राजनीतिक यात्रा एक ऐसे जननेता की कहानी है जिसने सत्ता नहीं, सेवा को साधन बनाया। चार दशक से अधिक समय में उन्होंने पंचायत से लेकर विधानसभा तक अपनी पहचान ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा से बनाई। गांवों में विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं को दिशा देने के उनके प्रयास ग्राम राजनीति को नई परिभाषा देते हैं। भले ही उन्होंने स्वयं विधायक पद का चुनाव नहीं लड़ा, पर कई विधायकों की डूबती नैया पार लगवाई। वे यह याद दिलाते हैं कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक सतत जिम्मेदारी है। रमेश वर्मा का नेतृत्व केवल निर्णयों में नहीं, बल्कि संवाद में दिखता है। वे लोगों की समस्याएँ सुनते हैं, अधिकारियों से समाधान करवाते हैं और परिणाम सामने आने तक उसका फॉलोअप करते हैं। इस व्यवहारिक राजनीति ने उन्हें एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

गांव की राजनीति को अक्सर स्वार्थ, गुटबाज़ी और जातिगत समीकरणों के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन कभी-कभी उसी मिट्टी से ऐसे लोग भी निकलते हैं, जो यह साबित कर देते हैं कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सच्चा रास्ता भी हो सकती है। हरियाणा के भिवानी ज़िले के छोटे से गांव बड़वा से निकलने वाले रमेश वर्मा इसी सोच का जीवंत उदाहरण हैं। उनके चार दशक से अधिक लंबे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि सेवा का संस्कार दिखाई देता है।

रमेश वर्मा की यात्रा उस पीढ़ी से शुरू होती है, जब पंचायत केवल निर्णय का मंच नहीं बल्कि संवाद का प्रतीक हुआ करती थी। वर्ष 1983 में उनके पिता किशना राम सिंहमार के ग्राम सरपंच चुने जाने के समय से ही उन्होंने प्रशासनिक कार्य, गांव के विकास की जरूरतों और जनहित के मुद्दों को करीब से देखा। यही अनुभव उनकी राजनीतिक सोच की नींव बना। उस दौर में युवा रमेश ने पंचायत के कार्यों में सहयोग कर यह सीखा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। राजनीति में यह सीख उन्हें आगे भी दिशा देती रही।

वर्ष 1996 में उन्होंने पहली बार जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भाग लिया। 10 उम्मीदवारों में द्वितीय स्थान प्राप्त करना उस समय न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि यह संकेत भी कि बड़वा का यह युवा अपने गांव से आगे सोचने लगा था। तीन साल बाद, 1999 में, जब उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा मार्केट कमेटी सिवानी (हल्का बवानी खेड़ा) का चेयरमैन नियुक्त किया गया, तब उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी को जनकल्याण की दृष्टि से निभाया। उस कार्यकाल में स्थानीय किसानों के हित, मंडी व्यवस्था की पारदर्शिता और व्यापारियों की सुविधाओं पर उनका ध्यान विशेष रहा।

रमेश वर्मा की राजनीति का दूसरा चरण 2005 में शुरू होता है, जब वे दोबारा अपने गांव के सरपंच चुने गए। पांच वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने जिस समर्पण से ग्राम पंचायत को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया, वह आज भी चर्चा का विषय है। सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, नालियां, स्कूल भवन और मंदिर-पार्क जैसी परियोजनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। लोगों का कहना है कि उन्होंने राजनीति को दिखावे का साधन नहीं, बल्कि समाज निर्माण का माध्यम बनाया।

2016 में जब वे पंचायती चुनाव में मात्र 71 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे, तब भी उन्होंने इसे पराजय नहीं, बल्कि जनता के नए मिज़ाज का सम्मान माना। यह विनम्रता और आत्मस्वीकार ही उन्हें आम नेताओं से अलग बनाती है। उस हार के बाद भी उन्होंने समाजसेवा का कार्य जारी रखा और अगले तीन वर्षों में लोहारू विधानसभा चुनाव (2019) में सक्रिय रूप से संगठन और प्रचार कार्य संभालकर यह साबित किया कि उनकी निष्ठा पद से नहीं, उद्देश्य से जुड़ी है। भले ही उन्होंने स्वयं विधायक पद का चुनाव नहीं लड़ा, पर कई विधायकों की 'डूबती नैया' पार लगवाई। यह उनकी रणनीतिक सूझबूझ और जनसंपर्क कौशल का प्रमाण था — वे हर मोर्चे पर पार्टी और समाज के हित में मजबूती से खड़े रहे।

सिर्फ राजनीति ही नहीं, रमेश वर्मा की पहचान एक समाजसेवी के रूप में भी गहरी है। ₹स्वच्छ भारत अभियान₹ के दौरान उन्होंने न केवल गांव में सफाई अभियान चलाया, बल्कि लोगों को व्यवहारिक रूप से स्वच्छता की आदत डालने की प्रेरणा दी। महिलाओं के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह (SHG) की शुरुआत की, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में उन्होंने राशन, मास्क और सैनिटाइज़र वितरण में सक्रिय भागीदारी निभाई, जबकि अधिकांश लोग भय से घरों में सीमित थे। उनके लिए सेवा किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती — वह जीवन का हिस्सा है।

युवाओं के लिए रमेश वर्मा ने कई खेलकूद प्रतियोगिताओं और करियर काउंसलिंग शिविरों का आयोजन करवाया। उनका मानना है कि गांव का युवा यदि सही दिशा और प्रेरणा पाए, तो उसे शहर की ओर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोच उन्हें स्थानीय स्तर पर शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है।

उनकी राजनीतिक शैली में सबसे उल्लेखनीय बात है पारदर्शिता और जवाबदेही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि किसी भी योजना या विकास कार्य में जनता की भागीदारी हो। गांव की बैठकों में हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होती रही। उनका यह विश्वास कि "राजनीति लोगों पर हुकूमत नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर सेवा करने का नाम है" — उनकी पहचान बन गया है।

रमेश वर्मा का नेतृत्व केवल निर्णयों में नहीं, बल्कि संवाद में दिखता है। वे लोगों की समस्याएँ सुनते हैं, अधिकारियों से समाधान करवाते हैं और परिणाम सामने आने तक उसका फॉलोअप करते हैं। इस व्यवहारिक राजनीति ने उन्हें एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। यही कारण है कि वे 40 से अधिक गांवों में विकास योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करवाने में योगदान दे पाए।

वर्ष 1983 से 2025 तक का उनका सामाजिक जीवन सम्मान और सीख दोनों से भरा है। हिसार और भिवानी के कई गांवों में उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक मंचों द्वारा सम्मानित किया गया। 2024 में स्थानीय अख़बारों में उन पर विशेष लेख प्रकाशित हुए, जिनमें उन्हें "जागरूक नेता और समाजसेवी" कहा गया।

रमेश वर्मा की राजनीति में जो सबसे अलग दिखाई देता है, वह है ईमानदारी की निरंतरता। अक्सर नेता चुनाव के समय जनता के बीच दिखते हैं, फिर पांच साल गायब रहते हैं, लेकिन रमेश वर्मा के मामले में यह पैटर्न उलटा है। वे हर परिस्थिति में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मौजूद रहते हैं — चाहे कोई समस्या हो या उत्सव। यह निरंतर जुड़ाव ही उन्हें "जनता का आदमी" बनाता है, न कि सिर्फ "पद का व्यक्ति।"

उनकी दृष्टि साफ है — राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, किसानों की सुरक्षा और महिलाओं-युवाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना। वे मानते हैं कि गांव और शहर के बीच विकास की खाई तभी पाटी जा सकती है, जब स्थानीय स्तर पर संसाधनों और अवसरों का समान वितरण हो।

आज जब राजनीति का बड़ा हिस्सा प्रदर्शन, बयानबाज़ी और प्रचार तक सिमट गया है, तब रमेश वर्मा जैसे नेता यह याद दिलाते हैं कि "नेतृत्व का मतलब लोकप्रियता नहीं, जिम्मेदारी होता है।" वे जनता को वोट बैंक नहीं, परिवार समझते हैं। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें "नेता" नहीं बल्कि "सेवक" कहकर बुलाते हैं।

हरियाणा की राजनीति में जहां युवा पीढ़ी में तेज़ी से बढ़ते स्वार्थ और लाभवाद के बीच ईमानदार नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही है, वहां रमेश वर्मा जैसे जनप्रतिनिधि उम्मीद की एक नई किरण हैं। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि गांव की गलियों से भी ऐसे नेता निकल सकते हैं जो प्रदेश और देश के स्तर पर नये मानक स्थापित करें।

आज जब लोकतंत्र को फिर से जनसंपर्क से जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है, तब रमेश वर्मा जैसे लोगों की कहानियाँ लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत करती हैं। वे उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिसमें नेता जनता से दूर नहीं, बल्कि जनता के साथ चलता है।

अगर भारत को सचमुच गांवों का देश कहा जाए, तो ऐसे नेताओं की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। क्योंकि गांव के नेता ही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होते हैं। और जब वह सीढ़ी मजबूत होती है, तभी ऊपर खड़ा ढांचा स्थायी रह सकता है। रमेश वर्मा जैसे जनप्रतिनिधि यही सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें केवल संविधान में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी में भी गहराई तक फैली रहें।

अंततः, रमेश वर्मा की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो राजनीति को नैतिकता से जोड़ती है। वे यह साबित करते हैं कि "राजनीति में रहकर भी साफ़ रहा जा सकता है, यदि नीयत साफ़ हो।" उनका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि जनसेवा यदि ईमानदारी से की जाए तो वह केवल गांव नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को भी उजाला देती है।

डॉ. कलाम – वह प्रकाश, जो युवा पीढ़ी को दिशा देता है

आकाश की अनंत ऊँचाइयों को छूने का साहस, ज्ञान की अथाह गहराइयों में उतरने की जिज्ञासा और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा – यही थे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के 'मिसाइल मैन' और 'जनता के राष्ट्रपति'। 15 अक्टूबर, उनकी जयंती, महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का उत्सव है, जो हमें उनके आदर्शों, सपनों और ज्ञान की अमर विरासत से जोड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन को 'रीडिंग इंस्पिरेशन डे' घोषित किया है, ताकि उनकी पुस्तक प्रेम और ज्ञान की भूख की भावना नई पीढ़ी में जागे। यह पहल एक आयोजन से कहीं बढ़कर है – यह एक संदेश है कि पढ़ाई वह शक्ति है, जो सपनों को उड़ान देती है और राष्ट्र को नई दिशा।

डॉ. कलाम का जीवन एक प्रेरक गाथा है, जो साधारण शुरुआत से असाधारण उपलब्धियों का प्रतीक है। रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में जन्मे, जहाँ उनके पिता नाविक और माँ गृहिणी थीं, संसाधनों की कमी ने कभी उनके सपनों को बंधन में नहीं बाँधा। बचपन में अखबार बाँटने से लेकर भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का नेतृत्व करने तक, उनका सफर दर्शाता है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत हर बाधा को परास्त कर सकती है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है।

डॉ. कलाम का नाम भारत के वैज्ञानिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इसरो और डीआरडीओ में उनके योगदान ने भारत को स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई। अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी भूमिका ने भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाया। लेकिन उनकी महानता केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। वे एक दूरदर्शी विचारक, लेखक और शिक्षक थे, जिनके लिए ज्ञान जीवन का आधार था। उनका विश्वास था कि पुस्तकें न केवल जानकारी देती हैं, बल्कि सृजनात्मकता, नैतिकता और जीवन के गहन दर्शन का द्वार खोलती हैं। उनका कथन, "सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें," आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है।

'रीडिंग इंस्पिरेशन डे' के रूप में उनकी जयंती मनाना एक दूरदर्शी कदम है। यह दिन केवल पुस्तकों की ओर ध्यान खींचने का अवसर नहीं, बल्कि युवाओं में जिज्ञासा, अनुशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का आह्वान है। डॉ. कलाम का जीवन सिखाता है कि पढ़ाई केवल डिग्री या नौकरी का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समृद्ध करने और समाज को बदलने का उपकरण है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में इस दिन उनकी पुस्तकों जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स के साथ-साथ उनके भाषणों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया जाता है। यह आयोजन बच्चों को समय प्रबंधन, निरंतर सीखने की आदत और नैतिकता का महत्व सिखाकर एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है।

डॉ. कलाम का जीवन अनुशासन और जिज्ञासा का अनुपम उदाहरण है। व्यस्त जीवन में भी वे सुबह जल्दी उठकर ध्यान करते, विचारों को कलमबद्ध करते और पुस्तकों में खो जाते। उनका विश्वास था कि छोटे-छोटे कदम, यदि सही दिशा में उठें, तो बड़े बदलाव लाते हैं। आज के युवाओं के लिए, जो त्वरित सफलता की चाह में धैर्य खो देते हैं, उनका यह संदेश अमूल्य है: सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं; यह कठिन परिश्रम, निरंतर सीखने और नैतिकता का फल है।

डॉ. कलाम का सपना केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था; वे एक सशक्त, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते थे। उनके लिए शिक्षा और विज्ञान का मकसद था समाज और राष्ट्र की सेवा। उनकी पुस्तकों और भाषणों में बार-बार यही गूंजता है कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनका विश्वास, "२०२० तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा," आज भी हमें सामूहिक और राष्ट्रीय सपनों के लिए प्रेरित करता है। युवाओं को सही दिशा मिले, तो भारत विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।

'रीडिंग इंस्पिरेशन डे' केवल पुस्तकें पढ़ने का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और समावेशिता का प्रतीक है। साधारण पृष्ठभूमि से आए डॉ. कलाम ने कभी जाति, धर्म या क्षेत्र को अपनी राह में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए सुलभ होने चाहिए। यह आयोजन ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचे, जहाँ पुस्तकों और संसाधनों की कमी है, ताकि हर बच्चे तक ज्ञान की रोशनी पहुँचे।

डॉ. कलाम की अनकही कहानियाँ भी उतनी ही प्रेरक हैं। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे सादगी से जीते और बच्चों से मिलने के लिए हमेशा समय निकालते। स्कूलों में जाकर वे छात्रों को विज्ञान, नवाचार और सपनों के लिए प्रेरित करते। उनकी पुस्तक माय जर्नी में साझा बचपन की सादगी और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी हिम्मत और मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

15 अक्टूबर केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प है। डॉ. कलाम का जीवन एक खुली किताब है, जिसका हर पन्ना प्रेरणा, अनुशासन और देशभक्ति की कहानी कहता है। 'रीडिंग इंस्पिरेशन डे' हमें सिखाता है कि पुस्तकें विचारों का खजाना हैं, जो सवाल उठाने की हिम्मत और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। इस दिन हम प्रण लें कि हम न केवल अपने लिए पढ़ेंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान अर्जित करेंगे।

डॉ. कलाम का सपना था एक ऐसा भारत, जो विज्ञान, शिक्षा और नैतिकता में विश्व का नेतृत्व करे। यदि हर युवा उनकी तरह जिज्ञासु, अनुशासित और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित बने, तो उनका सपना साकार होगा। यह दिन हमें यही संदेश देता है: पढ़ो, सीखो, सपने देखो और भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाओ।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

जातीय नफरत की सर्कस : विवेकहीन समाज की एक त्रासदी

सदियों से भारतीय समाज जातीय भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह नफरत केवल सामाजिक संरचना को नहीं, बल्कि इंसान के विवेक और संवेदना को भी कुंद कर चुकी है। हर निर्णय, हर दृष्टिकोण, हर न्याय आज जाति के तराज़ू पर तोला जाता है। जब तक समाज जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर न्याय-अन्याय के बीच अंतर करना नहीं सीखेगा, तब तक कुछ स्वार्थी और धूर्त लोग इस विभाजन की साज़िश में हमें अपनी सर्कस बनाते रहेंगे।

\- डॉ प्रियंका सौरभ

\- डॉ. प्रियंका सौरभ, लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार, हरियाणा

भारतीय समाज की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। पर इन जड़ों में कई ऐसी गांठें भी हैं, जिन्होंने इंसानियत को बाँट दिया है। जाति का विचार शुरुआत में शायद एक सामाजिक संगठन का ढांचा था, पर समय के साथ यह व्यवस्था अन्याय, भेदभाव और शोषण का औजार बन गई। ऊँच-नीच की मानसिकता ने समाज को वर्गों में बाँट दिया और इस बंटवारे ने इंसान की पहचान को उसके कर्म से हटाकर उसकी जाति से जोड़ दिया।

जब कोई समाज अपने नैतिक विवेक को खो देता है, तब वह अन्याय को सामान्य मानने लगता है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। जातीय सोच इतनी गहराई से हमारी मानसिकता में समा गई है कि लोग अन्याय को भी "अपनों के पक्ष में" देखकर सही ठहराने लगते हैं। किसी अपराधी की जाति अगर अपनी है, तो लोग उसे निर्दोष मान लेते हैं; और अगर पीड़ित किसी अन्य जाति का है, तो उसके दर्द के प्रति संवेदना गायब हो जाती है। यह वह बिंदु है जहां इंसानियत मर जाती है और जातिवाद जीत जाता है।

राजनीति ने जातिवाद को जीवित रखा है, बल्कि उसे हवा दी है। हर चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता नहीं, उनकी जातीय पहचान का हिसाब लगाया जाता है। नेता जानते हैं कि जातीय गोलबंदी उनकी सत्ता की नींव है, इसलिए वे समाज को एकजुट करने के बजाय बांटे रखना चाहते हैं। वोट के लिए जाति को हथियार बनाना सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह विभाजन न केवल लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है, बल्कि पीढ़ियों के मन में अविश्वास और घृणा बो देता है।

जातीय पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा का प्रसार भी कई बार समान अवसरों के बिना अधूरा रह जाता है। जब तक हर वर्ग को समान अवसर, समान मंच और समान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक जातीय सोच का अंत संभव नहीं है। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को स्वतंत्र सोचने और दूसरों के दुःख को समझने की क्षमता दे।

मीडिया समाज का दर्पण होता है। पर जब दर्पण ही धुंधला हो जाए, तो सच्चाई कैसे दिखाई देगी? जातीय हिंसा या भेदभाव की खबरें अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से तो दिखाई जाती हैं, पर उनमें इंसानियत की करुणा का अभाव होता है। जरूरत है कि मीडिया समाज में संवाद का माध्यम बने, न कि विभाजन का। पत्रकारिता का मूल धर्म है सत्य को सामने लाना — चाहे वह किसी जाति, वर्ग या धर्म के विरुद्ध क्यों न हो।

हर युग में कुछ ऐसे चालाक और धूर्त लोग रहे हैं जो समाज की कमजोरियों को भुनाते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर — वे हमें बाँटकर अपनी कुर्सी और शक्ति को सुरक्षित करते हैं। हम वही जनता हैं जो उनके शो में दर्शक बन बैठे हैं। वे खेल दिखाते हैं, हम ताली बजाते हैं — और हर बार यह सर्कस चलता रहता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें दर्शक नहीं, निर्णायक बनना होगा।

न्याय का अर्थ तभी पूरा होता है जब वह बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाए। न्याय का कोई रंग, धर्म या जाति नहीं होती। समाज को चाहिए कि वह "हम बनाम वे" की मानसिकता से बाहर निकलकर "सबके लिए न्याय" की भावना को अपनाए। यही लोकतंत्र का आधार है। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर जाति से ऊपर उठकर सोचने लगे, तो यह बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं होगा।

जातिवाद केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक मानसिक गुलामी है। यह हमें विवेकहीन, असंवेदनशील और विभाजित बनाता है। आज समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि हम अपने भीतर झाँकें और समझें कि असली पहचान हमारी जाति नहीं, बल्कि हमारा कर्म और हमारा चरित्र है। सदियों से जो दीवारें हमें बाँटती आई हैं, उन्हें तोड़ने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जब समाज न्याय के पक्ष में खड़ा होना सीख लेगा — बिना यह देखे कि पीड़ित या अपराधी किस जाति का है — तभी हम कह सकेंगे कि हमने सच्चे अर्थों में सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया है। अन्यथा यह जातीय सर्कस यूँ ही चलता रहेगा, और हम अनजाने में उसके दर्शक बने रहेंगे।

ट्रंप का टैरिफ़ आतंकवाद और उसके सबक़ : प्रभात पटनायक

अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें सिखाती हैं कि कोई देश टैरिफ तब लगाता है, जब उसे आयातित मालों से अपने घरेलू उत्पादकों की हिफ़ाजत करनी होती है। लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफों का मकसद इससे कहीं व्यापक है। ये टैरिफ तो एक सैन्य हस्तक्षेप की तरह या तख्तापलट की कोशिश की तरह या किसी आतंकवादी हमले की तरह हैं, जिनका मकसद ट्रंप की मर्जी के सामने दूसरे देशों को झुकाना है।

मिसाल के तौर पर भारत के वस्त्र निर्यातकों पर 50 फीसद टैरिफ का भार कोई इसलिए नहीं डाला गया है कि इसके जरिए किन्हीं अमेरिकी वस्त्र निर्माताओं को संरक्षण मुहैया कराया जाना है, बल्कि इसका मकसद तो भारत को ट्रंप की मर्जी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना ही है।

हम इसी से ट्रंप की टैरिफ नीति की असंगतियों की व्याख्या कर सकते हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप ने जो 50 फीसद टैरिफ लगाया है, कथित रूप से रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है। लेकिन, रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीददार, भारत से बड़ा खरीददार तो चीन है। इसके बावजूद, चीन से अमेरिका में ज्यादातर आयातों पर टैरिफ की दर 50 फीसद से कम है।

इस भिन्नतापूर्ण सलूक की वजह इस तथ्य में छुपी है कि ट्रंप का मानना है कि भारत को दबाव डालकर झुकाया जा सकता है, जबकि चीन को नहीं झुकाया जा सकता है। चीन तो जवाब में चोट कर के अमेरिका को ही दर्द दे सकता है, मिसाल के तौर पर रेअर अर्थ्स के निर्यात रोक कर तकलीफ दे सकता है, जबकि भारत ने अभी तक तो किसी जवाबी कार्रवाई की धमकी नहीं दी है। इस लिहाज से भारत, ब्राजील से भी अलग है, जो ऐसा अकेला देश है, जिस पर 50 फीसद टैरिफ लगाया गया है। ब्राजील ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ब्राजील के मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगाने का ट्रंप का प्रकट कारण, और भी अजीबोगरीब है। कहा जा रहा है कि यह, नव-फासीवादी पूर्व-राष्ट्रपति, जेअर बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाए जाने की सजा के तौर पर किया जा रहा है। बोल्सोनारो, पिछले चुनाव में हार गया था और ट्रंप का मानना है कि उसे सम्मान-सहित बरी किया जाना चाहिए। लेकिन, यह ट्रंप की उद्घतता का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। भारत और ब्राजील को छांटकर, 50 फीसद टैरिफ थोपने के लिए चुने जाने का असली कारण संभवत: यही है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ बन सकने वाले किसी भी संयुक्त मोर्चे को तोड़ा जाए और ऐसा किया जाए, तीसरी दुनिया के दो सबसे बड़े देशों को धमकाकर, इससे अलग होने के लिए मजबूर करने के जरिए।

नियंत्रणात्मक रणनीति ध्वस्त

टैरिफों का हथियार बनाया जाना, साम्राज्यवाद की एक पूरी तरह से नयी कार्यनीति है।

निरुपनिवेशीकरण के बाद ज्यादातर तीसरी दुनिया के देशों ने नियंत्रणात्मक रणनीति अपनायी थी, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती थी, घरेलू बाजार का प्रसार करती थी और घरेलू उत्पादन तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का विकास करने के लिए राज्य का और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करती थी। इस रणनीति के खिलाफ साम्राज्यवाद द्वारा लगातार लड़ाई छेड़े रखी गयी थी। और शुरुआत में इस लड़ाई का विचारधारात्मक घटक, पूर्वी एशिया की "चार की चौकड़ी" की तथाकथित सफलता की दुहाइयां देना था। ये चौकड़ी थी—हांगकांग, सिंगापुर, ताईवान और दक्षिणी कोरिया। इसी सिलसिले में विश्व बैंक ने "अंतर्मुखी" और "बहिर्मुखी" विकास रणनीतियों का विभेद गढ़ा था। पूर्वी एशियाई चौकड़ी की सफलता की दलील देकर, "बहिर्मुखी" विकास रणनीति की श्रेष्ठता के दावे किए जाते थे।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक बौद्धिक रूप से पूरी तरह से बेईमानी भरी दलील का इस्तेमाल किया जा रहा था कि पूर्वी एशियाई चौकड़ी में निर्यात तथा जीडीपी वृद्धि की जैसी दरों को हासिल किया गया था, वैसी दरें सभी देशों में हासिल की जा सकती हैं, बशर्ते सभी देश उनकी तरह "बहिर्मुखी" रणनीति पर चलें। यह दलील बेतुकी थी, क्योंकि सभी देशों को मिलाकर उनके निर्यात की वृद्धि दर की सीमाएं, विश्व बाजार की वृद्धि दर से तय होती हैं। इसका नतीजा यह है कि कुछ देशों में अगर कहीं तेज वृद्धि दर हासिल की जाती है तो, यह अन्य देशों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर रहने के बल पर ही हो रहा होगा। लेकिन, इस तर्क को इस पूर्वधारणा के सहारे खारिज कर दिया गया कि हरेक देश एक "छोटा सा देश" है, जो जितना चाहे निर्यात कर सकता है।

दो कारकों ने बहस का पलड़ा, साम्राज्यवादी दलील के पक्ष में झुका दिया था। पहला कारक तो, चीन की निर्यात सफलता का ही था। बेशक, यह सफलता एक पूरी तरह से भिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में और एक भिन्न विकास यात्रा पथ पर चलते हुए हासिल की गयी थी, फिर भी इसे सारी दुनिया के सामने "बहिर्मुखी" रणनीति की श्रेष्ठता को साबित करने वाली कामयाबी बनाकर पेश किया गया। दूसरा कारक था, विकसित दुनिया की पूंजी के प्रकटत: इसका इच्छुक होने का कि अपनी गतिविधियों को तीसरी दुनिया में ले जाए। तर्क दिया जा रहा था कि इससे पूंजीवाद का, तीसरी दुनिया की ओर प्रसरण होगा और यह विकसित तथा विकासशील दुनिया के अंतर को ही मिटा देगा। यह मान लिया गया था कि विकसित दुनिया के राज्य हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और अनंतकाल तक इसके चलते अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी के बढ़ने को देखते रहेंगे तथा आर्थिक गतिविधियों के इस तरह के तबादले को रोकने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं।

साम्राज्यवाद का शिकंजा कसा

बहरहाल, इन सभी कारकों ने बहस को नियंत्रणात्मक व्यवस्था के खिलाफ झुकाने का काम किया। अलबत्ता इस झुकाव का भौतिक आधार बड़े पूंजीपति वर्ग के वर्गीय हितों में था, जिसे वैश्विक हो जाने की संभावनाओं ने ललचाया था। और इसके पीछे शहरी उच्च मध्य वर्ग के हित थे, जिसके बच्चे बढ़े पैमाने पर विकसित देशों में बसने के लिए देश से बाहर जा रहे थे और इसलिए वह खुद को विकसित दुनिया से जितने घनिष्ठ रूप से जुड़ा देखता था तथा अब भी देखता है, उतने घनिष्ठ रूप से घरेलू मजदूरों तथा किसानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखता है। इसी बीच विश्व बैंक तथा आईएमएफ भी काफी सक्रिय हो गए। ऐसा खासतौर पर तब हुआ, जब तेल धक्कों के बाद तीसरी दुनिया के कई देश भुगतान संतुलन संकट की चपेट में आ गए। इन वित्तीय एजेंसियों ने तीसरी दुनिया के अनेक देशों में वित्त मंत्रालयों के अति-महत्वपूर्ण निर्णयकारी पदों पर अपने कर्मचारियों को बैठा दिया। इसका सिलसिला अफ्रीका से शुरू हुआ और बाद में अन्य देशों तक पहुंच गया। इसका मकसद नियंत्रणात्मक निज़ामों को भीतर से ध्वस्त करना था। भारत को इसका श्रेय देना होगा कि उसने सबसे अंत तक इसका प्रतिरोध किया। लेकिन, 1991 में आखिरकार उसने भी घुटने टेक दिए।

यहां इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि बाद में नव-उदारवादी निज़ाम के अंतर्गत क्या हुआ? बहरहाल, अब यह स्पष्ट है कि तीसरी दुनिया के देशों को ललचा कर विकसित दुनिया के बाजारों पर निर्भर बनाने और "नियम आधारित" अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद, साम्राज्यवाद अब टैरिफ के जरिए उन्हें धौंस में लेने की स्थिति में आ गया है, जिससे उन्हें अपने फरमान मानने के लिए मजबूर कर सके।

साम्राज्यवाद, तीसरी दुनिया के करोड़ों लाचार किसानों तथा मजदूरों को, जिसमें पचासों लाख महिला मजदूर भी शामिल हैं, रोजगार से बाहर कराने का खतरा पैदा कर, उन पर भारी बदहाली थोप सकता है। भारतीय कपास किसानों के साथ तो वह पहले ही यह कर भी रहा है। उन्होंने अपने यहां विशाल कृषि सब्सीडियां बनायी हुई हैं, जबकि मोदी सरकार ने पिछले ही दिनों आयातित कपास पर लगा 11 फीसद आयात शुल्क उठा लिया। इससे किसानों की और ज्यादा आत्महत्याएं अपरिहार्य हो जाएंगी, जबकि भारत के करोड़ों कपड़ा मजदूरों पर, 50 फीसद का अनाप-शनाप टैरिफ लगाए जाने के चलते, अमेरिकी बाजार के बंद होने से पड़ने वाले प्रतिकूल असर पर, रत्तीभर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। भारत के कपड़ा तथा वस्त्र निर्यातों के साथ ट्रंप के टैरिफ यही करने जा रहे हैं।

संक्षेप में यह कि ग़ज़ा में जो कुछ सबसे जघन्य रूप में हो रहा है, उसे अन्यत्र भी घटित कराया जा सकता है और यह सैन्य हस्तक्षेप के जरिए नहीं, टैरिफ आतंकवाद के जरिए, साम्राज्यवादी फरमान को मानने से इंकार करने वाले तीसरी दुनिया के देशों के साथ किया जा रहा होगा। यह साम्राज्यवाद का बदले की भावना के साथ अपना जोर दिखाना है।

नियंत्रणात्मक रणनीति निरुपनिवेशीकरण की पूरक

सबक यह है कि एक मुख्य रूप से घरेलू बाजार आधारित, आत्मनिर्भरता-उन्मुख, नियंत्रणात्मक विकास रणनीति, निरुपनिवेशीकरण का आवश्यक परिपूरक है, जैसा कि भारत और तीसरी दुनिया के अन्य देशों ने निरुपनिवेशीकरण के फौरन बाद पहचाना था। एक "बहिर्मुखी" विकास रणनीति तो तीसरी दुनिया के देशों को साम्राज्यवाद के फरमान का चाकर बना देती है क्योंकि अन्य कारणों के अलावा तीसरी दुनिया के ये देश, साम्राज्यवादी बाजार पर निर्भर हो जाएंगे।

हमें किसानों के साल भर लंबे आंदोलन का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने हमारे देश को अपनी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का त्याग करने और अमेरिका से खाद्यान्न के आयातों पर निर्भर होने से रोक दिया। हमारे खाद्यान्न के लिए, अमेरिका से आयातों पर निर्भर हो जाने ने तो, भारत पर अपनी मर्जी थोपने के लिए, साम्राज्यवाद के हाथों में और भी असरदार हथियार थमा दिया होता। जो साम्राज्यवादी ताकत ग़ज़ा के लोगों के नरसंहार में मिलीभगत कर सकती है, क्या उसे अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं के खिलाफ किसी तीसरी दुनिया के देश के चलने की सूरत में, उसे खाद्यान्न आयातों से वंचित करने के जरिए, भारत जैसे किसी देश में अकाल भड़काने में खास हिचक होगी?

इसलिए, भारत जैसे किसी देश के लिए यह जरूरी है कि अपनी विकास रणनीति को बदले। इससे, पुरानी नियंत्रणात्मक रणनीति पर ही लौटने का अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बजाए, जरूरत एक ऐसी नियंत्रणात्मक रणनीति के अपनाए जाने की है, जो अंतर्निहित रूप से भूमि सुधारों को लागू करने के जरिए, कृषि को बढ़ावा देने के माध्यम से, मेहनतकश जनता के पक्ष में आय का पुनर्वितरण करे और कल्याणकारी राज्य के कदमों के जरिए सामाजिक मजदूरी बढ़ाने के माध्यम से, घरेलू बाजार के आकार को बढ़ाते रहने के लिए काम करे।

कोई कह सकता है कि मोदी सरकार ने 15 अगस्त को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में जिन रियायतों की घोषणा की है, उनके जरिए यही तो करने का प्रयास किया गया है। लेकिन, ऐसा दावा बेतुका होगा। हालांकि, जीएसटी में दी जा रही वास्तविक रियायतें, जो न तो मुख्यत: मेहनतकश जनता को दी जा रही हैं और न उनकी भरपाई ही अमीरों पर कर लगाकर की जाने वाली है, हमने तत्काल जो अनुमान लगाया था, उससे थोड़ा-सा ज्यादा रहने जा रहा है। (यह जीडीपी का 0.1 फीसद नहीं, 0.6 फीसद रहने जा रहा है और 0.32 लाख करोड़ नहीं, 1.95 लाख करोड़ रुपए रहने जा रहा है।) फिर भी यह दयनीय ढंग से थोड़ा रहने जा रहा है। एक ऐसे वैकल्पिक विकास यात्रापथ के लिए, जो कल्याणकारी राज्य के कदमों को सबसे ऊपर रखता हो, सरकार द्वारा जीडीपी का कम से कम 10 फीसद अतिरिक्त रूप से खर्च किए जाने की जरूरत होगी।

इसके अलावा सरकार को उन मजदूरों की तकलीफें दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे, जिनके रोजगार पर ट्रंप के टैरिफों की कड़ी मार पड़ने जा रही है। इस तथ्य को देखते हुए कि साम्राज्यवाद टैरिफों को हथियार बना रहा है, इन चोटों के नुकसान से उबरने के लिए निर्यात सब्सीडियां देने जैसे कदम शायद पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप उस स्थिति में टैरिफ और भी बढ़ा सकता है। फिर भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के ऊपर से, जैसी कार्रवाई चीन तथा ब्राजील कर रहे हैं, इस तरह के कदमों को आजमाया जा सकता है। इसके अलावा वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने की सक्रिय कोशिशें की जानी चाहिए। इसके अलावा जो इन प्रहारों के शिकार होने जा रहे हैं, उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक मौकों की तलाश किया जाना भी जरूरी है।

मोदी सरकार इस दिशा में कुछ कर तो नहीं ही रही है, वह वास्तव में अमेरिका को खुश करने के लिए अन्य क्षेत्रों में उसे रियायतें देने की ही कोशिशें कर रही है, जैसे भारत में कपास के तटकर मुक्त आयातों की इजाजत देना, जिसकी भारतीय किसानों पर कड़ी मार पड़ने जा रही है। इतना ही नहीं, यह सरकार ठीक इसी मुकाम पर उस मनरेगा पर खर्च में कटौतियां कर रही है, जो ग्रामीण भारत में मुसीबत के मारे लोगों के लिए एक जीवन-रेखा मुहैया करा सकती है।

(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं।)

बदलते दौर में मल्टी कैरियर एप्रोच से सफलता

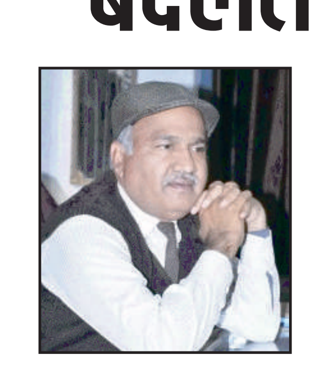

विजय गर्ग

कैरियर की दुनिया लगातार बदल रही है। तकनीक, शिक्षा, रोजगार और समाज की गति इतनी तेज है कि अब पूरी जिंदगी एक पेशे के साथ चिपके रहना व्यावहारिक नहीं रह गया। यह सफलता के लिए भी सुरक्षित विकल्प नहीं है। इसलिए अब बड़ी तेजी से मल्टी कैरियर एप्रोच की सोच विकसित हो रही है। पूरी दुनिया में आज के युवा एक कैरियर पर अपनी जिंदगी का दांव नहीं लगा रहे। इसलिए कई क्षेत्रों में काम करने की रोजगार की दुनिया में सहज प्रवृत्ति पैदा हो रही है।

(इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मल्टी कैरियर को आसान बना दिया)

पारंपरिक सोच रही है कि पढ़ाई-लिखाई करके किसी एक कैरियर को अपनाया जाए। लेकिन आज के तकनीक प्रधान समय में परिस्थितियां अलग हैं। लोग एक ही समय पर कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोशल मीडिया में बेहद स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। वहीं कई शिक्षक कोचिंग से भी कमाई करते हैं। कई मल्टी टैलेंट व रुचि के चलते दूसरा काम करते हैं लेकिन इस सबके लिए बेहद कर्मठता व स्मार्टनेस चाहिये।

कैरियर की दुनिया लगातार बदल रही है। तकनीक, शिक्षा, रोजगार और समाज की गति इतनी तेज है कि अब पूरी जिंदगी एक पेशे के साथ चिपके रहना व्यावहारिक नहीं रह गया। यह सफलता के लिए भी सुरक्षित विकल्प नहीं है। इसलिए अब बड़ी तेजी से मल्टी कैरियर एप्रोच की सोच विकसित हो रही है। पूरी दुनिया में आज के युवा एक कैरियर पर अपनी जिंदगी का दांव नहीं लगा रहे। इसलिए कई क्षेत्रों में काम करने की रोजगार की दुनिया में सहज प्रवृत्ति पैदा हो रही है। यह केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि भविष्य में कैरियर की ठोस गारंटी और विकल्प के रूप में उभरा है।

एक ही समय पर कई क्षेत्रों में काम

दरअसल सालों से कैरियर को लेकर पारंपरिक सोच रही है कि पढ़ाई-लिखाई करके किसी एक कैरियर के साथ पूरी जिंदगी का नाता जोड़ा जाए। लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। लोग एक ही समय पर कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोशल मीडिया में बेहद स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। यू-ट्यूब से वो अपनी इस टैलेंट की बदौलत अच्छा-खासा कमा रहे हैं। कई शिक्षक हैं जो बतौर शिक्षक जितनी तनख्वाह पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो ऑनलाइन कोचिंग के जरिये कमाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए और कैरियर की गारंटी के लिए जरूरी है कि एक ही कैरियर पर पूरी जिंदगी का दांव न लगाएं। इसलिए आज बड़ी तेजी से मल्टी कैरियर एप्रोच उभर रही है और कार्पोरेट जगत में इसे किसी तरह की खामी मानने की जगह एक नई स्मार्टनेस का दर्जा मिलता जा रहा है।

अनिश्चितता और असुरक्षा भी वजह

दरअसल बदलते समय में मल्टी कैरियर एप्रोच जरूरत भी बन गई है। वास्तव में अनिश्चितता और असुरक्षा किसी भी क्षेत्र में कब आ धमके, आज गारंटी के साथ यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए किसी भी क्षेत्र में अचानक आयी मंदी, नौकरी का संकट, तेजी से तकनीकी बदलाव, ऐसी अनेक समस्याओं का एकमात्र हल यही है कि हम एक ही समय में एक से ज्यादा कैरियर में हाथ आजमाएं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बनाया आसान

वास्तव में इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मल्टी कैरियर को आसान बना दिया है। अब घर बैठे ही दूसरा काम भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भी मल्टी कैरियर एप्रोच किसी तरह का दुस्साहस नहीं बल्कि सामान्य गतिविधि बन गई है। मल्टी कैरियर एप्रोच हमेशा कमाई या ज्यादा इंकम के लिए ही नहीं होता बल्कि कई बार हम एक ही काम करते करते रचनात्मक रूप से बोर हो जाते हैं। कई लोग एक ही साथ कई तरह की रुचियों वाले होते हैं। दूसरा कैरियर ऐसे लोगों के लिए भी तनावमुक्ति का जरिया होता है।

नये संपर्क बनाने का मौका

मल्टी कैरियर एप्रोच के कई फायदे हैं। इससे आर्थिक स्थिरता कैरियर संबंधी सुरक्षा हासिल होती है। खास करके जब बड़ी तेजी से और जल्दी जल्दी नये नये रुझान कैरियर के बाजार में देखने को मिल रहे हों। वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने से हमारे काम के साथ व्यक्तिगत संबंधों का दायरा भी बढ़ता है। हम ज्यादा से ज्यादा नये लोगों से जुड़ते हैं और हमारे पास नई-नई सफलताओं के लिए अवसर भी काफी हो जाते हैं। हालांकि एक साथ जब हम एक से ज्यादा कैरियर की नाव में सवार होते हैं, तो कई बार एक के कारण दूसरा काम प्रभावित होता है। लेकिन यह भी तो फायदा मिलता है कि एक से ज्यादा क्षेत्रों में सक्रिय होने के कारण हमें ज्यादा चीजें सीखने का मौका मिलता है। इससे दिमाग सक्रिय और अद्यतन बना रहता है।

आत्मविश्वास व सामाजिक प्रतिष्ठा

एक से ज्यादा क्षेत्रों में कैरियर बनाने से कई तरह की रुचियां और जुनून हमारे साथ बने होते हैं, जिससे हम किसी एक के मुकाबले कम बोर होते हैं। दरअसल हर कोई अपने मुख्य काम से संतुष्ट होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पत्रकार, पत्रकारिता के साथ-साथ गायन के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रहा है, तो उसे दोनों क्षेत्रों की असुरक्षा से मुक्ति मिलती है और यही सुरक्षाबोध उसे दोनों क्षेत्रों में बेहतर करने का आत्मविश्वास देता है। कई बार लोग मल्टी कैरियर एप्रोच के जरिये ज्यादा सफल रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी कोई काम असुरक्षाबोध से ग्रस्त होकर नहीं करते। इसलिए उनके काम में एक आत्मविश्वास की झलक मौजूद रहती है। इसके अलावा आजकल मल्टी कैरियर एप्रोच एक सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान का भी हिस्सा है। अगर कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा क्षेत्रों में सक्रिय है, तो आजकल उसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाला समझा जाता है।

कर्मठ, स्मार्ट होना जरूरी

मल्टी कैरियर एप्रोच की अपनी चुनौतियां भी हैं। यह एप्रोच जहां आकर्षक और फायदेमंद है, वहीं यह हर समय सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा आपसे अलर्ट रहने की मांग करता है। समय प्रबंधन में आपको हर समय परीक्षा से गुजरना होता है। क्योंकि दो क्षेत्रों में समय का प्रबंधन काफी कठिन होता है। अगर आपके एप्रोच में स्मार्टनेस न हुई तो यह फायदे की जगह नुकसान का कारण भी बन सकता है। दरअसल मल्टी कैरियर एप्रोच आम लोगों के लिए नहीं है, ये बेहद कर्मठ, स्मार्ट और हर समय सजग रहने वाले लोगों के लिए है।

मानसिक दबाव का जोखिम

मल्टी कैरियर एप्रोच हमें मानसिक और शारीरिक रूप से दो गुना थकाता भी है। लगातार अलग-अलग तरह के काम करते रहने से हम कई बार जबर्दस्त मानसिक दबाव का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो लोग मल्टी कैरियर एप्रोच के बारे में सोच रहे हों, उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इसे पूरी सजगता के साथ मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से इसे मैनेज नहीं कर पाते तो आपके दोनो कामों में इसका असर दिखेगा। आप किसी भी काम में उत्कृष्टता नहीं हासिल कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी कैरियर एप्रोच आजमाने के पहले आपके अंदर इस बात को लेकर एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य हो वर्ना आप इस दो नाव की सवारी से फिसल सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

संपादकीय

चिंतन-मनन

लाइब्रेरीज ऑन द गो: बस स्टैंड को ज्ञान के केंद्रों में बदलना

विजय गर्ग

सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, विशेष रूप से बस स्टैंड में पुस्तकालयों को एकीकृत करने की अवधारणा वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है, साक्षरता को बढ़ावा देने, पढ़ने वाली सामग्री को सुलभ बनाने और रचनात्मक सीखने के लिए अक्सर डाउनटाइम क्षणों का उपयोग करने के लिए एक अभिनव समाधान के रूप में कार्य कर रही है। ये पहल बस की सांसारिक प्रतीक्षा को बौद्धिक समृद्धता के अवसर में बदल देती हैं। दर्शनः प्रतीक्षा में पढ़ना बस स्टैंड पर पुस्तकालय के पीछे का मुख्य विचार लोगों से मिलना है जहां वे हैं। बस स्टैंड और टर्मिनल स्वाभाविक रूप से एक साथ आने वाले लोगों, छात्रों और यात्रियों के लिए व्यस्त होते हैं जिनके पास मिनटों या घंटों का समय है। इन स्थानों में किताबें और अध्ययन सामग्री डालकर, आयोजक ₹प्रतीक्षा समय₹ का लाभ उठाते हैं, जिससे यह ₹पढ़ने के समय₹ बन जाता है

साक्षरता को बढ़ावा देनाः डिजिटल स्क्रीन के वर्चस्व वाले युग में, ये पुस्तकालय लोगों को भौतिक पुस्तकों से पुनः जुड़ने और पढ़ने का प्रेम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सुलभताः वे ज्ञान तक पहुंच को लोकतंत्रीकृत करते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक सार्वजनिक पुस्तकालयों की कमी होती है, ग्रामीण सेटिंग्स या ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास समर्पित पुस्तकालय का दौरा करने का समय या साधन नहीं हो सकता।

एक ट्रस्ट-आधारित मॉडलः इनमें से कई सेटअप स्व-सेवा, विश्वास आधारित प्रणाली पर काम करते हैं, अक्सर इस सिद्धांत का पालन करते हैंः ₹आप ले सकते हैं, आप वापस आ सकते हैं इससे सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। सफल मॉडल और पहल बस स्टैंड लाइब्रेरी मॉडल के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं

ओपन-एक्सेस बस स्टॉप लाइब्रेरीज (भारत): कर्नाटक जैसे राज्यों में, पहलों ने सैकड़ों गांव के बस स्टॉप्स को खुली पहुंच वाली पुस्तकालयों में बदल दिया है, जिन्हें कभी-कभी 'बुक नेस्ट' कहा जाता है। इनमें आमतौर पर कहानियों और सामान्य ज्ञान से लेकर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए सामग्री तक की पुस्तकों का एक विविध संग्रह होता है, तथा इन्हें अक्सर समर्पित पुस्तकालयकार के बिना चलाया जाता है, जो पुस्तकें उधार लेने और वापस करने के लिए जनता की ईमानदारी पर निर्भर करता है।

परिवर्तित बस/वाहन पुस्तकालय (भारत और वैश्विक): कुछ परियोजनाओं ने पुरानी, बंद बसों को मोबाइल लाइब्रेरी या बस स्टेशनों पर स्थिर पढ़ने के कमरे में बदल दिया है। उदाहरण के लिए, पुणे महानगर परिवाहन महमांडल लिमिटेड (पीएमपीएल) ने एक स्क्रैप बस को मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय में बदल दिया है, जिसमें निःशुल्क वाई-फाई भी शामिल है यह मॉडल एक पूर्ण, संरक्षित पढ़ने का वातावरण प्रदान करता है।

सामुदायिक केंद्रों (कश्मीर) में ₹स्ट्रीट लाइब्रेरीज₹ः दक्षिण कश्मीर से एक उत्साहवर्धक उदाहरण के रूप में, भारतीय सेना ने स्थानीय छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और उच्च अध्ययनों के लिए पुस्तकों से भरी पुरानी बस स्टैंड को 'सड़क पुस्तकालय' बना दिया।

एकीकृत डिजिटल और प्रिंट स्टेशन (सिंगापुर): अधिक तकनीकी रूप से उन्नत मॉडलों में, एक बस स्टॉप मुद्रित पुस्तकों का घूर्णन करने वाला चयन प्रदान कर सकता है तथा साथ ही ग्राहकों को राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली से ई-पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए इंटरैक्टिव स्टेशन भी उपलब्ध करा सकता है। प्रभाव और भविष्य इन पहलों का प्रभाव केवल पुस्तकों को वितरित करने से परे है। वे सकारात्मक सार्वजनिक स्थान बनाते हैं, पारगमन बिंदुओं का माहौल बढ़ाते हैं और अक्सर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र बौद्धिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण हो सकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

उत्सव के पटाखे और वायु प्रदूषण शिशुओं की फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा उनकी रक्षा करने के तरीके

विजय गर्ग

उत्सव के पटाखे समारोह, खुशी और रंग का प्रतीक हैं। लेकिन जबकि वयस्क दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेते हैं, बच्चे धुएं, बारीक कणों और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों के कॉकटेल में चुपचाप सांस ले रहे हैं। उत्सव समाप्त होने के बाद ये प्रदूषक हवा में लंबे समय तक रह सकते हैं, जिससे मोटी धुंध पैदा होती है जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होती है।

डॉ. अकुश गार्ग के अनुसार ₹क्योंकि शिशुओं की फेफड़ों और प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, इसलिए वे अपने शरीर के वजन से अधिक तेज सांस लेते हैं, जिससे उन्हें प्रदूषण से संबंधित क्षति का सामना करना पड़ता है

शिशुओं के श्वसन स्वास्थ्य पर प्रदूषण क्या करता है प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से खांसी, नाक की भीड़, सांस लेना और श्वसन संक्रमण हो सकता है। दीर्घकालिक संपर्क में आने से फेफड़ों का विकास धीमा हो सकता है, अस्थमा और जीवन के बाद एलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है। जिन शिशुओं में समय से पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें इससे भी अधिक खतरा होता है।

डॉ. गार्ग ने आगे कहा कि ₹बेबियों के श्वसन मार्ग

वयस्कों की तुलना में संकुचित होते हैं।₹ प्रदूषकों से सूजन या चिड़चिड़ापन की थोड़ी मात्रा भी वयस्कों पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है। खराब वेंटिलेशन वाले इनडोर स्थानों में अपरिपक्व प्रतिरक्षा प्रणाली और लंबे समय तक संपर्क जोड़ना, तथा शिशु अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं

यह केवल बाहरी धुआं ही खतरा नहीं है। त्यौहारों के दौरान, विशेष रूप से बिना उचित वेंटिलेशन वाले घरों में भी इनडोर हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पटाखे के कण घर में फंस सकते हैं, जिससे शिशुओं का एक्सपोजर समय बढ़ जाता है। माता-पिता को वायु शुद्धिकरण उपकरण का उपयोग करने, प्रदूषण के चरम घंटों में खिड़कियां बंद रखने और प्राकृतिक रूप से हवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करने के लिए शांति लिली या मकड़ियों जैसी इनडोर पौधों का परिचय देने की सलाह दी जाती है।

माता-पिता सरल कदम उठा सकते हैं वायु प्रदूषण से शिशुओं की रक्षा करना जटिल नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञ अनुशंसा करते हैं

आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान या तुरंत बाद शिशुओं को घर में रखें। यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो बच्चों को हल्के कपास के कपड़े पहनें। प्यूरिफायर या वायु शुद्ध करने वाले संयंत्रों के साथ इनडोर हवा की सफाई बनाए रखें। प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए वृद्ध शिशुओं को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खिलाएं। चिड़चिड़ापन कम करने के लिए शिशुओं को हाइड्रेटेड और साफ रखें। धूम्रपान वाले क्षेत्रों से पूरी तरह बचें और पर्यावरण के अनुकूल, क्रैकर-मुक्त समारोहों को प्रोत्साहित करें। त्योहार का मौसम खुशी और उत्सव के लिए है, लेकिन यह शिशुओं के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं आना चाहिए। स्वच्छ, शांत समारोहों का समर्थन करने से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है बल्कि अगली पीढ़ी के लिए स्वस्थ फेफड़ों को भी सुनिश्चित किया जाता है। जैसा कि डॉ. अंकुश गार्ग कहते हैं, ₹स्वच्छ वायु की सुरक्षा से बच्चों के लिए आनंददायक त्योहार और स्वस्थ फेफड़े सुनिश्चित होते हैं

शिशुओं के फेफड़ों का स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और बच्चे, बच्चों पर पटाखे के प्रभाव, नवजात स्वास्थ्य, पर्यावरण-अनुकूल दिवाली, शिशुओं को प्रदूषित होने से बचाना, शिशुओं में श्वसन स्वास्थ्य, दिवाली सुरक्षा युक्तियाँ, शिशुओं के लिए वायु शुद्धिकरण

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् सड़क कुर चंद एमएचआर मलोट

भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

विजय गर्ग

नीट पीजी : भारत में हर साल हज़ारों युवा डॉक्टर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शामिल होने के इच्छुक होते हैं। हालाँकि, बढ़ती ट्यूशन फीस, आवास की लागत और रहने का खर्च युवा चिकित्सा पेशेवरों को अपनी योजनाओं को साकार करने से रोक सकता है। चिकित्सा शिक्षा, विशेष रूप से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, छात्रों से शैक्षणिक प्रदर्शन के अलावा कई अन्य निवेशों की भी मांग करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य और प्रतिभाशाली छात्र अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से वंचित न रहें, कई सरकारी विभागों, राज्य विभागों, विश्वविद्यालयों और कंपनियों ने नीट पीजी परीक्षा देने की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अनुदान और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के मेडिकल करियर को सहारा देना है। भारत में नीट पीजी छात्रों के लिए उपलब्ध प्रमुख वित्तीय सहायता विकल्पः

सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्तियाँ भारत सरकार अपनी चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के इच्छुक जूनियर डॉक्टरों के लिए कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाती है। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के विभिन्न शिक्षा विभागों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ अक्सर योग्यता या आवश्यकता के आधार पर दी जाती हैं, और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस, रहने का भत्ता और शोध लागत को कवर कर सकती हैं। निम्नलिखित योजनाएँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं:

● उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना - यह योजना उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों वाले छात्रों की सहायता के लिए है। यह योजना स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के दौरान ट्यूशन और रखरखाव दोनों लागतों में सहायता करती है। ● आईसीएमआर, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, चिकित्सा अनुसंधान-उन्मुख छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करता है। वे नैदानिक परीक्षणों, महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों और जैव-चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित शैक्षिक अध्ययनों या शोध परियोजनाओं के लिए छात्रवृत्ति निधि प्राप्त कर सकते हैं। ● एम्स और पीजीआईएमईआर छात्रवृत्तिः जिन छात्रों को एम्स और पीजीआईएमईआर जैसे शीर्ष रैंकिंग वाले मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए स्वीकार किया जाता है, उन्हें शैक्षणिक प्रदर्शन और निरंतर प्रदर्शन के लिए संस्थागत छात्रवृत्ति मिल सकती है, जो आमतौर पर पूर्ण या आंशिक पाठ्यक्रम शुल्क के साथ-साथ उन्नत अनुसंधान जारी रखने के लिए वजीफा भी होती है।

आधारित छात्रवृत्ति स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंचने के लिए सामुदायिक/वित्तीय लागत पर स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहचान की गई कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणियों के दोनों छात्रों को सक्षम करेगी, जिससे अंततः स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में समानता और विविधता प्रदान होगी।

● राज्य चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिः कुछ राज्यों में भारत भर के राज्य या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातक चिकित्सा अध्ययन करने वाले निवासियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मूल पात्रताः पात्र होने के लिए आवेदकों को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनके पास वैध नीट पीजी क्रेडेंशियल्स हों और उन्हें पुरस्कार देने वाले संगठन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक और आय मानदंडों को पूरा करना होगा। ये छात्रवृत्ति न केवल वित्तीय सहायता हैं, बल्कि छात्रों को अपने क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर की शिक्षा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके शैक्षणिक उत्कृष्टता का साधन भी है।2. राज्य और आरक्षित श्रेणी सहायता भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली समावेशन और समान अवसर पर भी जोर देती है। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार एसी, एसटी, उबीसी, ईडबयुएस तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क छूट प्रदान करती है।

डॉ. एससी/एसटी छात्रों के लिए आंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्रीय और राज्य सरकारों का सहयोग है, जो स्नातक और अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययनों के लिए ट्यूशन, रखरखाव भत्ते, प्रबंध प्रिंटिंग और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशासित विश्वविद्यालयों के शीर्ष पर स्नातक होने वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) के लिए योग्यता-समर्थन छात्रवृत्ति शुरू की जाती है। यह वित्तीय सहायता छात्रों को आर्थिक और योग्यता मानदंडों के आधार पर उनकी ट्यूशन और रहने की लागत का ध्यान रखने के लिए धन प्रदान करती है। पात्रता मानदंडः छात्रों को एक विशिष्ट समुदाय या आरक्षित समूह से होना चाहिए, उनके पास उचित दस्तावेज होना चाहिए और पारिवारिक आय आमतौर पर Rs. प्रति वर्ष 8 लाख, तथा उन्हें मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/विश्वविद्यालय में नामांकित किया जाना चाहिए।

पात्रता मानदंडः छात्रों को एक विशिष्ट समुदाय या आरक्षित समूह से होना चाहिए, उनके पास उचित दस्तावेज होना चाहिए और पारिवारिक आय आमतौर पर रु. प्रति वर्ष 8 लाख, और उन्हें मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय में नामांकित किया जाना चाहिए। ये राज्य/और समुदाय-आधारित छात्रवृत्ति पहचान की गई कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणियों के दोनों छात्रों को स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंचने के लिए सामुदायिक/वित्तीय लागत पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी, जिससे अंततः स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में समानता और विविधता मिलेगी। 3. एनआईएमएस संस्थागत सहायता नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस) जैसे शैक्षिक संस्थानों ने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सुलभता और पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता पहल लागू की है। एनआईएमएस शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यापक भागीदारी दोनों में छात्रों की सहायता के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है। वित्तीय सहायता के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं

● मेरिट-आधारित छात्रवृत्तिः बहुत उच्च नीट पीजी रैंकिंग या उन छात्रों के आधार पर जो निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ● जरूरत-आधारित ट्यूशन छूटः आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए, एनआईएमएस ट्युशन छूट या कम शुल्क प्रदान करता है ताकि किसी भी व्यवहार्य छात्र को अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। ● आंतरिक छात्रवृत्तिः एनआईएमएस में उन छात्रों के लिए भी धन उपलब्ध है जो एक अभिनव परियोजना या चिकित्सा अध्ययन बनाने में लगे हुए हैं जिनका सामाजिक पहलू या प्रभाव होता है। ये पहल शोध और साक्ष्य-आधारित अभ्यास की संस्कृति बनाने का प्रयास करती हैं जो स्नातकोत्तर छात्रों के बीच टिकाऊ होगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, एनआईएमएस उन अवसरों का निर्माण करते हुए करुणापूर्ण, सक्षम और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो वित्तीय कारणों से योग्य चिकित्सा छात्रों को इस पेशे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। 4. शिक्षा ऋण और अनुदान कई नीट पीजी आवेदकों के लिए, शिक्षा ऋण उनकी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए वित्तपोषण का एक विश्वसनीय स्रोत बने हुए हैं। मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए कई राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों में वास्तव में लचीले भुगतान और आकर्षक ब्याज दरें उपलब्ध हैं। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें

● विद्या लक्ष्मी पोर्टलः एक केंद्र सरकार द्वारा समर्थित संगठन जो वन-स्टॉप दुकान के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से छात्र एक ही समय में विभिन्न बैंकों से ऋण कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल छात्रों को कई बैंकों की शर्तों की तुलना करने में आसानी से मदद करता है। ● डॉ. अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर ब्याज अनुदानः इस योजना के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छात्रों के परिवारों को स्थगित अवधि के दौरान ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि वे पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपने वित्त का ध्यान रखें। ● बैंक-विशिष्ट चिकित्सा शिक्षा ऋणः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और एचडीएफसी जैसे प्रमुख बैंकों में नीट पीजी छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण उपलब्ध हैं जो ट्यूशन, छात्रावास शुल्क, पुस्तकें और दैनिक जीवन व्यय को कवर करते हैं। यदि छात्र उच्च रैंक से नीचे गिर जाते हैं या प्रतिष्ठित चिकित्सा कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो कई बैंकों ने बीमा छोड़ दिया है। टिपः छात्र अपने ऋण पात्रता को मजबूत करने के लिए एक मजबूत शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखें और प्रवेश, शुल्क संरचना और पारिवारिक आय प्रमाण दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।5. निजी और एनजीओ अनुदान सरकारी सहायता के अलावा, चिकित्सा शिक्षा का वित्तपोषण निजी संस्थाओं, ट्रस्ट और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से आता है जो अनुदान, छात्रवृत्ति और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए 1। सर रतन टाटा ट्रस्ट मेडिकल छात्रवृत्तिः ये स्वास्थ्य विज्ञान में योग्य छात्रों को आंशिक धन प्रदान करते हैं। 2. उच्च शिक्षा के लिए आदित्य बिरला छात्रवृत्तिः यह कार्यक्रम चिकित्सा सहित किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता वाले उत्कृष्ट छात्रों की तलाश करता है। 3. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) फेलोशिप और पुरस्कारः आईएमए वार्षिक छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन और सामुदायिक सेवा प्रदर्शित करने वाले स्नातकोत्तर छात्रों और शोधकर्ताओं को फ़ेलोशिप प्रदान करता है। 4. एचडीएफसी बैंक परिवर्तन छात्रवृत्तिः यह कार्यक्रम चिकित्सा विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को स्कूल में बने रहने और अपनी शिक्षा न खोने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये निजी और गैर-सरकारी परियोजनाएं अक्सर प्रतिस्पर्धी होती हैं और शैक्षणिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों पर आधारित होती हैं, तथा उन छात्रों को पुरस्कृत करती हैं जो न केवल शैक्षिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपने समुदायों में भी योगदान देते हैं। 6. योग्यता और नीट पीजी रैंक का लाभ उठाना नीट पीजी में उच्च स्कोर, अच्छे ग्रेड और प्रकाशनों वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय अतिरिक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है। अधिकांश विश्वविद्यालय, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, मानक परीक्षणों, प्रकाशित अनुसंधान और अन्य उपलब्धियों के माध्यम से आवेदकों की क्षमताओं का आकलन करते हैं। पात्रता बढ़ाने के तरीके

पात्रता बढ़ाने के तरीके 1। शैक्षणिक उपलब्धियों, नीट पीजी स्कोर और प्रकाशनों के दस्तावेज बनाए रखें। 2. शिक्षाविदों या प्रशिक्षकों से प्रामाणिकता और अनुसंधान क्षमता का समर्थन करने वाले पत्र प्राप्त करें। 3. प्रारंभिक आवेदन करें, और समय सीमा से पहले सभी सहायक दस्तावेजों की सटीकता की जांच करें। बदले में, छात्रों के पास छात्रवृत्ति या फेलोशिप प्राप्त करने का बेहतर मौका हो सकता है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती लागत निर्धारित और असाधारण उम्मीदवारों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सरकारी वित्तपोषण कार्यक्रमों के विभिन्न मंत्रालयों, एनआईएमएस जैसे संस्थानों से छात्रवृत्ति अवसरों और निजी तथा/या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित एवं वित्त पोषित दर्जनों अनुदान अवसरों के साथ सभी छात्रों के लिए धन उपलब्ध है। छात्रों को एनएसपी (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) और विद्या लक्ष्मी जैसी सरकारी पोर्टलों के साथ-साथ एमईआर की वेबसाइट पर प्रक्रिया में पहले ही गहन शोध करने और आवेदन करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को नई पहल के लिए विधायी वित्तपोषण संबंधी विचारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने पर भी काम करना चाहिए, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ बढ़ावा दिया जाएगा तथा वर्ष में जारी किया जाएगा। विभिन्न तरीकों से वित्तपोषण की संभावनाओं पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि छात्र सहायता कार्यक्रम प्रतिभा, समर्पण और करुणा को भारत में चिकित्सा पेशेवरों के भविष्य का आधार बनाते हैं, वित्तीय पृष्ठभूमि नहीं। निर्दिष्ट नीट पीजी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले चिकित्सा छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध धन का उपयोग कर सकते हैं तथा भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के उत्पादक और योगदानकर्ता सदस्यों के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया मृतक के परिजन को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश यह फैसला राज्य की सभी नगर निगमों पर होगा लागू

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई, ठाणे समेत राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है और सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस गंभीर समस्या का संज्ञान लिया और नगर निगम प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि भविष्य में गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में यदि किसी की जान जाती है तो संबंधित नगर निगम 50 हजार रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का मुआवजा देगी। यह फैसला राज्य की सभी नगर निगमों पर लागू है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का कारण नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा है भविष्य में यदि गड्ढों के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संबंधित ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में संबंधित ठेकेदार से दुर्घटना के कारण हुई क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के लिए प्रत्येक नगर निगम में एक अलग समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।

दुर्घटना पीड़ित अब मुआवजे के पात्र गड्ढों या खुले नालों के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों में, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को अब 6 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। साथ ही चोट की प्रकृति के आधार पर 50 हजार रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रत्येक नगर निगम इन मुआवजे के दावों की जाँच और सही आंकड़ा निर्धारित करने के लिए एक अलग समिति गठित करे। मुआवजा देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा और दावे की तिथि से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुआवजा राशि पर ब्याज भी लगाया जाएगा, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है।

क्या है याचिका ? वर्ष 2018 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल के मुद्दे पर विभिन्न निर्देश जारी किए थे। एडवोकेट रुजु ठक्कर ने अदालत में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य के सभी नगर निगम इन निर्देशों के अनुसार सड़कों का रखरखाव करने में विफल रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल एक विस्तृत आदेश के साथ इस याचिका का निपटारा कर दिया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार, साथ ही जनता के हित और गड्ढों के मुद्दे की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने मूल सुमोटो जनहित याचिका को पुनः सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इस याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अपने 77 पृष्ठों के फैसले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार और संबंधित नगर निगम प्रशासन गड्ढों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अदालत ने रेखांकित किया है कि गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए न केवल ठेकेदार, बल्कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए, आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने इन आदेशों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जाँच के लिए अगली सुनवाई 21 नवंबर तक स्थगित कर दी है।

वैष्णो देवी तीर्थयात्रा बच्चों को पारंपरिक मूल्यों से परिचित कराती है

बच्चों के साथ वैष्णो देवी यात्रा के कई लाभ हैं, जिनमें बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा मिलना, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, और सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण में ट्रैकिंग और पिकनिक जैसे अनुभवों का आनंद लेना शामिल है। इसके अलावा, वैष्णो देवी तीर्थयात्रा बच्चों को पारंपरिक मूल्यों से परिचित कराती है और एक संपूर्ण पारिवारिक अनुभव प्रदान करती है।

झारखंड का आबुआ सरकार अब दलाल - बिचौलियों की सरकार बन गयी है : बाबूलाल मरांडी

आदिवासी एवं सनातनियों की आवादी घट रही है झारखंड में

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

जमशेदपुर। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हातियापाटा में आयोजित बूथ सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आबुआ सरकार अब आबुआ नहीं रहा।

सरकार दलाल व बिचौलिया के हाथों में चला गया। हेमंत सोरेन सरकार में कहीं बिना पैसा का कहीं काम नहीं होता। यहां बहाली नहीं नौकरी बेची जाती है। बूथ सम्मेलन में गुड़ाबांदा, सिंहपुरा, फारेस्ट ब्लाक व भालकी पंचायत के 21 बूथों से कार्यकर्ता शामिल थे ।

बाबूलाल मरांडी शुरू से ही अपने भाषण में हेमंत सोरेन सरकार पर ताबोड़तोड़ हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में राज्य के लोगों को मुफ्त में बालू मिलता था, परंतु हेमंत सोरेन ने दिल्ली, कोलकाता व मुंबई से दलालों को लेकर आए है।

उन्होंने लोगों से कहा कि अभी गलती सुधारने को मौका है। उन्होंने मुखर होकर घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। कहा कि झारखंड में तेजी से आदिवासी और सनातनियों की आबादी घट रही, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। जिससे झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा।

यहां आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। पाकुड़, साहिबगंज मे घुसपैठियों का आधार कार्ड बन रहा है, परंतु हेमंत सोरेन सरकार मान नहीं रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले बार राज्य में भाजपा की सरकार लानी है। तब जाकर झारखंडियों का भला होगा। बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ही आदिवासियों को सम्मान देती है।

कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो ने उप चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, प्रभारी बड़कुवर गागराई, पूर्व प्रत्याशी लखन मार्डी, अभय सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व प्रत्याशी बाबुलाल सोरेन ने मंडल समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की।

वहीं, जादूगोड़ा के राखा कापर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन समेत कई मौजूद थे।

चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीते कुछ वर्षों में विकास की रफ्तार थम सी गई है। उन्होंने कहा सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रोजगार, खदान व योजनाओं के काम रुके पड़े हैं।

भ्रष्टाचार और ठहराव ने पूरे सिस्टम को जकड़ लिया। भाजपा का उद्देश्य प्रदेश में एक बार फिर स्थिर और जवाबदेह शासन लाना है, ताकि लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। झारखंड में अपराध, लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। बालू घोटाले से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह रिश्वत का बोलबाला है।

रामदयाल मुंडा संस्थान में धरती आबा आदिवासी फ़िल्म फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ

आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और सृजनशीलता को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को रांची स्थित डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान में प्रथम धरती आबा जनजातीय फ़ल्मि फेस्ट 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह महोत्सव केवल फिल्मों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारी आदिवासी पहचान, परंपरा और जीवन दर्शन का उत्सव है। फिल्म एक सशक्त माध्यम है जो जनजातीय भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और संघर्षों को दुनिया के सामने लाती है। राज्य सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह फिल्म महोत्सव झारखंड सरकार एवं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति, समुदाय या जनजातीय जीवन पर फिल्म बनाई जाए, तो उसके दृश्य और कथानक यथार्थ पर आधारित हों — न कि काल्पनिक या भ्रामक। कला और सिनेमा का दायित्व समाज की सच्चाई को उजागर करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सही परिप्रेक्ष्य में अपनी जड़ों को पहचान सकें। इस पहल से आदिवासी कलाकारों और युवाओं को अपनी अभिव्यक्ति का एक सशक्त मंच मिलेगा, जिससे वे अपने समुदाय की वास्तविक कहानियों को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर प्रस्तुत कर सकेंगे। चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और भाषाई विविधता का संरक्षण भी है। ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में सेतु का कार्य करेंगे।

महोत्सव का उद्देश्य देश के जनजातीय समाज की विविध कला, संस्कृति, परंपरा और संघर्षों को सिनेमा के माध्यम से राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय फिल्म निर्माताओं, शोधकर्ताओं और कलाकारों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आदिवासी जीवन के गहरे सरोकारों को साझा किया। फेस्टिवल के दौरान झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों की 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। इनमें पलाश "हेंडे सोना एंड ब्लैक गोल्ड", "फूलो", "कुसुम", "नाची से बाचीऽ जैसी चर्चित फिल्मों शामिल हो

इस अवसर पर विभाग के सचिव कृपा नन्द झा, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक करमा ज़िम्पा भुट्टिया, विशेष सचिव बागे तथा कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने से झारखंड हाईकोर्ट फिर नाराज

तीन हफ्ते में आयोग को अनुशंसा भेजने हेतु सरकार को स्पष्ट निर्देश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची , झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। इस संबंध में दायर एक अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे तीन हफ्ते के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा भेजें।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण की ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के नाम पर चुनाव लंबे समय तक नहीं टाल सकती। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय मांगा, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने आयोग को अगली सुनवाई के दौरान यह बताने का निर्देश दिया कि वह कितनी शीघ्रता से चुनाव करा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को निर्देश दिया था कि राज्य के नगर निकाय चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराए जाएं। इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है। इसे लेकर कोर्ट में खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है।

झारखंड में 48 शहरी निकाय हैं। इनमें से 12 शहरी निकायों के चुनाव जून 2020 से लंबित हैं, जबकि अन्य नगर निकायों का कार्यकाल भी अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका ।

जस्टिस आनंदा सेन की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार , गृह सचिव वंदना डाडेल, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

महिलाएं कार खरीदेंगी, सरकार भुगतान करेगी!

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : दिवाली से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। फ्लैगशिप योजना सुभद्रा की पूरे राज्य में चर्चा रही। अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना आ रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। जिसका नाम होगा आत्मनिर्भर महिला सुनायक या आम सुनायक योजना। इस योजना के तहत, सरकार राज्य की महिलाओं के लिए कार खरीदेगी। महिलाएँ ऋण लेकर कार खरीदेंगी और राज्य सरकार सारा ब्याज देगी। सरकार महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी योजना शुरू करने जा रही है।

जो महिलाएँ ऋण लेकर कार खरीदना चाहती हैं, उनके लिए राज्य सरकार कार खरीदेगी। प्रत्येक महिला को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और जो महिलाएँ कार खरीदने के लिए ऋण लेती हैं, वे इसे 5 वर्षों के भीतर चुका सकती हैं। यह सच है कि महिलाएँ ऋण लेकर कार खरीदेंगी, लेकिन सारा ब्याज सरकार देगी।

प्रत्येक महिला को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। सरकार 1100 महिलाओं को 4 वर्षों में कार खरीदने और उन्हें टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। परिणामस्वरूप, महिलाओं को अब ब्याज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रत्येक महिला को बैंक से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। महिलाएँ 5 वर्षों में ऋण की किश्तें चुकाएँगी और राज्य सरकार 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगी। राज्य सरकार ने वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की इस योजना को मंजूरी दे दी है। 23 तारीख़ को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भ्रामक सूचनाओं के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई पर ज़ोर दिया

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस. गोपालन (वी.पी.एस.) की अध्यक्षता में विशेष व्यापक पुनरीक्षण पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. लक्ष्मी प्रसाद साहू, जनसंपर्क अधिकारी श्री सौरभ प्रधान और सभी जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालन ने विशेष व्यापक पुनरीक्षण के मुख्य उद्देश्य और समयबद्ध आवश्यकता, मतदाताओं की पात्रता, भ्रामक सूचनाओं से निपटने पर विस्तृत जानकारी दी और जमीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा करने में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। चुनाव आयोग ने कई वर्षों तक ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करके पूरे विश्व में एक विशेष सम्मान अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि उस सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भ्रामक और भ्रामक सूचनाओं से उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने को अत्यधिक महत्व देता है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम न जोड़ा जाए, और ओडिशा में इसी को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य किए जा रहे हैं।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. साहू ने एक पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों को विशेष गहन सुधार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों की भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भ्रामक सूचनाओं, जैसे कि एक साथ कई लोगों के नाम हटाए जाएँगे, बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है, बिना मकान संख्या वाले घर, एक पते पर कई लोगों का पंजीकरण, के बारे में पता चलने के बाद, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों को सही जानकारी जनता तक पहुँचाकर गलत सूचनाओं का शीघ्रता से निपटान करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भेजी जाने वाली नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ और सूचनाओं को जमीनी स्तर पर जनता की जागरूकता और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सोशल और अन्य मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जाना चाहिए।

स्लाइट के नौ फैकल्टी मेंबर और एक पूर्व शोध छात्रा विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल

लोगोंवाल, 14 अक्टूबर (जगसीर सिंह)- संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (स्लाइट), लोंगोवाल ने निर्देशक डॉ. प्रो. मणिकांत पासवान के मार्गदर्शन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 की शीर्ष 2% वैज्ञानिक सूची में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया,

अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2025 की विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की रैंकिंग जारी की है, जो उद्धरण मापदंडों पर आधारित है और वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली शोधकर्ताओं को उजागर करती है। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एक प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशक, एल्सेवियर बीवी, द्वारा तैयार की गई है। इसमें वैज्ञानिकों को 22 क्षेत्रों और 174 उप-क्षेत्रों में साइंस-मेट्रिक्स वर्गीकरण के अनुसार विभाजित किया गया है। यह रैंकिंग उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को मान्यता देने का एक विश्वसनीय मानक है। इसमें स्लाइट लोंगोवाल के नौ फैकल्टी मेंबरों और एक पूर्व शोध छात्रा ने विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। इसमें

संस्थान के डॉ. पी. एस. पनेसर, डॉ. सी. एस. रियार, डॉ. धीरज सूद, डॉ. अश्वनी अग्रवाल, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सुरिंदर सिंह, डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. ए. के. सिंगला और डॉ. एच. आर. घाटक शामिल हैं, तथा

डॉ. सुरिंदर सिंह के मार्गदर्शन में पूर्व शोध छात्रा डॉ. वीरपाल कौर को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

स्लाइट के निदेशक डॉ. मणिकांत पासवान ने उल्लेख किया कि इस वर्ष की उपलब्धि पिछले वर्ष की रैंकिंग से बेहतर है, जिससे संस्थान की शोध प्रतिष्ठा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है। उन्होंने संस्थान में शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईक्यूएसी के अध्यक्ष डॉ. कमलेश प्रसाद और शोध एवं परामर्श के अधिष्ठाता डॉ. सुरिंदर सिंह के प्रयासों की भी सराहना की। यह उपलब्धि डॉ. मणिकांत पासवान, निदेशक के मार्गदर्शन में स्लाइट की शोध और नवाचार के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

"हरियाणा" के ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों एवं सारथी बंधुओं का खून-पसीना नहीं, बहता सैलाब

लूट की क्रूर चक्की में पिसते लाखों परिवारों की आंसू-रक्त मिश्रित चित्कार - अब बहुत हुआ ! अन्याय की आग से उगलती हुंकार, या फिर राष्ट्रीय विद्रोह का तांडव !

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली : यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एन्ड सारथी एसोसिएशंस (यूएफटीटीएसए) - राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने हरियाणा के ट्रक उद्योग के सीने पर गहरे चुभते उन कांटों पर न केवल आंसुओं से भरी चित्कार की है, बल्कि एक क्रांतिकारी हुंकार भी भरी है जो दुर्व्यवस्था की पहाड़ों को हिला देगी। डॉ. यादव की आवाज, जो खुद एक ट्रांसपोर्टर परिवार से निकली है, कांपते हुए फूट पड़ी - आंखों में आग, सीने में दर्द, और मुट्ठी में न्याय की आस ललकारः ₹हमारे ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्टर एवं सारथी बंधु - ये वो संग्रामी योद्धा हैं जो रात-दिन, वर्षा-तूफान में अपनी जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की धमनियों में माल रूपी खून प्रवाहित करते हैं। ये वो मजदूर, मालिक व संग्रामी हैं जिनके पसीने की बूंदें सड़कों पर सोने की तरह चमकती हैं, लेकिन आज ? ये सरकारी तंत्र के लुटेरों के जाल में फंसकर पिस रहे हैं, सरकारी उदासीनता के जहर से तड़पकर मर रहे हैं, और अपने बच्चों के भविष्य को मिट्टी में मिलते देख चीख रहे हैं ! हरियाणा का ट्रकिंग सेक्टर, जो अरबों-खरबों की अर्थव्यवस्था का धड़कता दिल है, अब टूटे-फूटे कांच की तरह सड़कों पर बिखर रहा है - हर टुकड़ा एक परिवार का टूटा सपना, हर खनक एक विधवा की चीख। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि जीवंत दर्द की किताब हैः एक पिता का बेटे को ट्रक की चाबी थमाते हुए रो-रोकर बेहोश होना, एक मां का चालक बेटे की लाश घर लौटते देख बाल नोचना, एक बहू का ससुराल में अपमान सहते हुए आंसू निगलना। हम चुप नहीं रहेंगे ! ये आंसू अब खून बनेंगे, ये चीखें तूफान बनेंगी ! तत्काल न्याय दो, वरना यूएफटीटीएसए का राष्ट्रीय आंदोलन सड़कों पर आग की लपटें बिखेर देगा - ट्रक रुकेंगे, तो राष्ट्र की सांस रुक जाएगी !"

घटनाक्रम सहित तथ्यात्मक दर्द की अनंत दास्तां के तहत आंसुओं-खून से लथपथ एक क्रूर, अमानवीय यात्रा

हरियाणा का ट्रकिंग उद्योग, जो 31,702 किलोमीटर की पथरीली सड़कों पर रेंगता हुआ, भारत की कुल माल ढुलाई का 34% बोझ अकेले कंधों पर लादे हुए है, दशकों से एक अनंत यातना-कुंड की आग में धीरे-धीरे दहक रहा है। ये आंकड़े नहीं, बल्कि रूह कंपाने वाली, दिल दहला देने वाली कहानियां हैं - जहां हर ट्रक की गर्जना के पीछे एक परिवार का कराह है, हर इंजन की धड़कन के साथ एक दिल का फटना और आंसुओं का रिसना। आइए, इस दिल दहला देने वाली कालानुक्रमिक यात्रा में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर आंसू का सैलाब, खून का फव्वारा, और निराशा का काला बादल छाया है। ये तथ्य केवल कागजों के नहीं, बल्कि जीते-जागते दर्द के प्रमाण हैं-

दशक पूर्व का खोया हुआ स्वर्णिम युगः सपनों का महल, जो धूल में मिल गया (2010-2015): सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे जिलों में 2,000 से अधिक ट्रक गर्जन करते हुए फर्राते भरते थे, जैसे शेरों का झुंड। मजबूत यूनियनों की छांव में ट्रांसपोर्टर न केवल परिवारों को पालते, बल्कि सभी तीज त्यौहार व बेटियों की शादियां धूमधाम से मनाते, गांवों में सम्मान से सिर ऊंचा रखते। फ्रेट रेट्स निष्पक्ष थे, ईंधन सस्ता, सड़कें उबड़ खाबड़ तो थी किन्तु टोल के नाम पर खून नहीं चुस्ती थी, यूँ कहें सपनों सी थी लेकिन सरकारी नीतियों की अनदेखी ने धीरे-धीरे इस व्यवसाय में वो जहर घोल दिया, जो आज उनके रग-रग में जहर सा दौड़ रहा है। एक बुजुर्ग ट्रक मालिक, रामस्वरूप जी, की डायरी से झलकः ₹मेरा ट्रक मेरा बेटा था - वो गाड़ी चलती और मैं सपने बुनता। आज वो कब्र खोदने वाला हथौड़ा बन गया। मेरी बेटी की शादी के लिए बेचा, लेकिन आंसू न बिके।₹ ये दौर वो था जब ट्रकिंग गर्व था, आज अपमान।

यूनियन विघटन का दिल फाड़ देने वाला क्रूर आघात - आवाजों का गला घोंटना (2012-2015): सिरसा ट्रक यूनियन, जो 2,000+ वाहनों की एकजुट चीख थी, एक दशक पूर्व जबरन कुचल दी गई। सरकार ने पुनर्गठन का दरवाजा बंद कर दिया, जैसे कोई तानाशाह। नतीजा ? ट्रांसपोर्टरों की पुकार हवा में गुम, बिखरी हुई। व्यापारियों के मनमाने फ्रेट रेट्स (प्रति किमी मात्र 40-50 रुपये) ने उन्हें गुलामों की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया, जबकि जीविका के लिए कम से कम 90 रुपये जरूरी। आज सिरसा में सिर्फ 600 ट्रक बचे हैं - आधे से ज्यादा दम तोड़ चुके या बेचे गए। 10,000-12,000 परिवार भूखे-प्यासे सड़कों पर भटक रहे, बच्चे स्कूल छोड़ चुके, महिलाएं मजदूरी करने को मजबूर। एक ट्रांसपोर्टर, श्यामलाल की आह सुनिएः ₹मेरा ट्रक बेच दिया कर्ज चुकाने को, लेकिन बेटे की आंखों में वो भूख की चीख मिट न सकी। रातें काटता हूं, सपने में यूनियन की गूंज सुनाई देती है - लेकिन सुबह उदासीनता का फिर वही सन्नाटा।₹ ये विघटन केवल संगठन का नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों का अंत था।

2022-2023: आंतरिक घावों और बाहरी तीरों का खूनी, अमर्याद तांडव - दर्द का दोहरा प्रहार-82 फ्लीट मालिकों पर आधारित गहन अध्ययन चीख-चीखकर बयान देता है - 77.4% ट्रक मालिकों की शिक्षा महज 12वीं तक सीमित, 74.2% की वार्षिक आय 5 लाख से कम, जैसे गरीबी का जाल। आंतरिक दर्द गहरा - लोडिंग की अक्षमता (0.867) ने हर यात्रा को नुकसान का गर्त बना दिया, वित्त प्राप्ति की कठिनाई (0.758) ने कर्ज के पहाड़ खड़े कर दिए, बीमा क्लेम की लंबी देरी (0.610) ने अस्पताल के बिलों में डुबो दिया - एक दुर्घटना ने परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया। भुगतान विलंब (0.849) ने घरों के चूल्हे बुझा दिए, अकुशल चालक (0.589) ने दुर्घटनाओं का सैलाब ला दिया - हर हादसा एक परिवार का कत्लेआम। बाहरी जख्म और भी घातक - सरकारी नीतियां (0.619) ने पीठ में छुरा घोंप दिया, ब्रोकरों का अंधेरा राज (0.907) ने लूट का तांडव मचा दिया - वे फ्रेट का 20-30% काट लेते, बाकी चालक को। तकनीकी पिछड़ापन (0.895) ने भविष्य चुरा लिया, अधिकारियों की उदासीनता (0.802) ने आंसू बहाए - चेकपोस्ट पर घंटों इंतजार, रिश्वत की मांग। ईंधन मूल्य (0.756) ने जेबें फाड़ दीं - यात्रा खर्च का 50% से ज्यादा, देरी से 14.7 अरब डॉलर का राष्ट्रीय खून बहा। अध्ययन की 69.58% विविधता दो कारकों से जुड़ी - आय और ट्रकों की संख्या - लेकिन ये तो टूटे दिलों की धड़कनें हैं, जहां हर धड़कन दर्द की और टूटे बिखरे आस व विश्वास की। एक चालक, हरि सिंह की पुकारः ₹मैं सड़क पर मरूं या घर लौटूं, दोनों तरफ मौत का साया। मेरी पत्नी रोटियां सेंकते हुए रोती है, बच्चे भूखे में सोते हैं। क्या यही हमारा भाग्य है ?"

2024: हिट-एंड-रन कानून का क्रूर, निर्लज्ज प्रहार - राष्ट्रीय हड़ताल का आंसू-खून मिश्रित विद्रोह- जनवरी 2024 को नई भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों में 10 वर्ष की सजा के प्रावधान ने चालकों के सीने पर बिजली गिरा दी, जैसे मौत का फरमान। हरियाणा से लेकर देशभर में ट्रक रुक गए - पंजाब-हरियाणा में ईंधन पंपों पर अफरा-तफरी का तमाशा, राजमार्ग सुनसान कब्रिस्तान। हड़ताल एक पूरे माह चली, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन सरकार ने फिर भी इसे स्थगित नहीं किया - घाव तो वही नासूर बन सड़ते रहे व गहराते रहे, भय का साया गहरा और भी गहरा। चालकों का डर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है - हर मोड़ पर सजा का भूत। फ्लीट मालिकों के आंसू सूख ही नहीं रहे थे, क्योंकि चालक भागने लगे। एक विधवा, सरिता देवी की चीख सुनिएः ₹मेरा पति एक रात की दुर्घटना में चला गया - ट्रक पलटा, जान गई। अब ये कानून मुझे भी सजा देगा क्या ? मेरे बच्चे अनाथ, मैं विधवा - क्या अपराध किया भला हमने ? सड़कें हमें रोटी तो देती हैं, लेकिन मौत भी !₹

2025-पतन का चरमोत्कर्ष - आंसुओं का महासैलाब, निराशा का काला अंधकार (जनवरी-अक्टूबर): एनसीआर में पुराने ट्रकों (10 वर्ष से अधिक पुराने) पर सख्त प्रतिबंध और लाखों-करोड़ों का जुर्माना - ट्रक की कीमत 60-70 लाख, बिक्री मूल्य महज 10-15 लाख, जैसे लूट खसोट का अंतिम वार। चालक संकट गहरा- 100 ट्रकों पर सिर्फ 52 चालक उपलब्ध, 90% नशे की चपेट में फंसे - दर्द की दवा बन गया अब जहर। स्वास्थ्य ह्रास ने भयंकर रूप लिया डायबिटीज, हृदय रोग, थकान से दुर्घटनाएं। वेतन विलंबित (मासिक 12,000 रुपये), परिवार भूखे। सामाजिक कलंक अमिट- बेटियां ट्रक चालक से विवाह से इनकार, शादियां टूट रही। ऑनलाइन पेमेंट की अशिक्षा ने और पीड़ा दी - ऐप्स समझ न आए, पैसे लुटे बारम्बार। खराब सड़क अवसंरचना ने रखरखाव लागत दोगुनी कर दी - गड्ढों में ट्रक फंसते और चालक घायल। जुलाई 2025 की श्रम कानूनों के विरुद्ध राष्ट्रीय हड़ताल ने हरियाणा रोडवेज को हिला दिया, लेकिन ट्रक सेक्टर के आंसू अनदेखे रहे - जैसे कोई भूला हुआ अध्याय। एक युवा चालक, विजय की डायरी सेः ₹ट्रक चलाना मेरी किस्मत थी, अब ये मेरी कफन। रातें डरावनी, दिन थकान भरे। मां की गोद में लौटना चाहता हूं, लेकिन कर्ज का बोझ लगातार दबा रहा। क्या हम इंसान हैं या सड़क का मलबा ?"

ये समस्याएं आंकड़े नहीं, बल्कि टूटे परिवारों की चीखें, विधवाओं की कराहें, अनाथों की पुकारें हैं। एक ट्रांसपोर्टर रोते बिलखते हुए चिल्लायाः "ट्रक मालिक होना गर्व का ताज था, अब अपमान का बोझ।" एक चालक की आह- "बेटी किसी ट्रक चालक को जीवनसाथी नहीं बनाना चाहती - हमारा पाप क्या है ? सड़क पर जान हथेली पर रखना ?" ये दर्द हर घर में घुस चुका - आत्महत्याओं का सिलसिला, तलाकों का तूफान, बच्चों का स्कूल छोड़ना।

मांगें-आंसुओं से सने, खून से रंगे न्याय की क्रांतिकारी पुकार

डॉ. राजकुमार यादव ने आंसू पोछते, मुट्ठी तानते हुए ये मांगें दोहराईं, जो लाखों दिलों की धड़कन, रगों का खून हैं - इन्हें अनसुना करने का मतलब राष्ट्र को ललकारनाः

फ्रेट रेट्स में तत्काल न्यूनतम वृद्धि (कम से कम 90 रुपये प्रति किमी) और यूनियनों का पूर्ण पुनर्गठन - ताकि गुलामी की जंजीरें चटक जाएं, फिर वही बोली की आवाजें गूंजें।

ईंधन मूल्य पर सख्त नियंत्रण कर 60 रूपये प्रती लीटर, टोल टैक्स में 60% छूट, पुराने ट्रकों पर पूर्ण क्षमा और आधुनिकीकरण सब्सिडी - ताकि जेबें न फटें, ट्रक फिर गर्व से सड़कों पर दौड़ें।

चालकों के लिए स्वास्थ्य कार्ड, पेंशन योजना (मासिक 10,000 रुपये), नशा मुक्ति केंद्रों का जाल - ताकि मांएं बेटों को खोएं नहीं, परिवार टूटें नहीं।

हिट-एंड-रन कानून में तत्काल संशोधन (सजा 2 वर्ष तक, मुआवजा अनिवार्य) और चालक सुरक्षा बीमा - ताकि सड़कें कब्रिस्तान न बनें, हर यात्रा जीवन बने व जीवंत हरियाली 1

वित्तीय सहायता (कम ब्याज लोन), तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 100% सब्सिडी, और ट्रेनिंग सेंटर - ताकि सपने फिर जागें, पिछड़ापन मिटे।

ब्रोकरों पर शीघ्र सख्त कानून, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम - ताकि लूट रुके, पारदर्शिता आए।

"सरकारें बदलती हैं, चुनाव आते-जाते हैं, लेकिन हमारे सारथी बंधुओं का दर्द स्थिर है, कोई सुधार नहीं - ये आंसू पहाड़ बनेंगे और ये चीखें सुनामी। अगर 15 दिनों में ये जख्म न सीजे, तो यूएफटीटीएसए राष्ट्रीय हड़ताल की आग सुलगाएगा - हर राजमार्ग अवरुद्ध, हर ट्रक सड़क पर विद्रोह। ट्रक रुकेंगे, तो राष्ट्र का दिल रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था खून उगलेगी ! क्या आप भी सुन रहे हैं ये चीखें ? क्या आपका विवेक जागेगा, या इतिहास हमें फिर भी दोषी ठहराएगा ?"

दीवाली के मद्देनज़र डीजीपी गौरव यादव ने पूरे पंजाब में पुलिस की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट बढ़ाने के दिए निर्देश

पाकिस्तान नशा-आतंकवाद को बढ़ावा देकर पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है; पंजाब पुलिस उसके नापाक मंसूबों को कर रही है नाकाम : डीजीपी गौरव यादव

डीजीपी ने तरनतारण और बटाला जिलों में सुरक्षा समीक्षा बैठकों की की अध्यक्षता

203 विदेशी हैंडलर्स की हुई पहचान, रेड कॉर्नर/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू : डीजीपी गौरव यादव

सितंबर 2024 से अब तक 26 आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, 90 आरोपी गिरफ्तार

तरनतारण/बटाला/चंडीगढ़, (साहिल बेरी)

आगामी दिनों में दीवाली के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को सभी जिला पुलिस प्रमुखों को पूरे राज्य में पुलिस बल की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट नाकों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए।

डीजीपी गौरव यादव, जो एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान और एडीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद के साथ तरनतारण और बटाला जिलों में सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे, ने नशा-आतंकवाद और संगठित अपराध से उत्पन्न खतरों पर चर्चा की। उन्होंने त्योहारों के सीजन के दौरान की जाने वाली तैयारियों और पुलिस बल की तैनाती की भी विस्तृत समीक्षा की।

मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में नशा-आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान नशा-आतंकवाद को बढ़ावा देकर पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके नापाक मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है।"

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ड्रोन और अन्य माध्यमों से पंजाब में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी कर रहा है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस हवाई खतरे से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैनात एंटी-ड्रोन सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है।

आतंकवाद विरोधी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने 90 आरोपियों को गिरफ्तार कर 26 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इन आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद, हैंड ग्रेनेड और आरडीएक्स बरामद किया गया है, जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि संगठित अपराध से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई है, जिनमें कुछ गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए और कहा कि अपराध के माहौल को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और पेशेवर जांच आवश्यक है।

उन्होंने खुलासा किया कि आतंकवादी नेटवर्क या संगठित अपराध से जुड़े 203 विदेशी हैंडलर्स की पहचान की गई है। उन्होंने कहा, "इन अपराधियों को भारत लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।"

डीजीपी ने चल रही नशा-विरोधी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' की भी समीक्षा की। अभियान के परिणाम साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से अब तक पंजाब पुलिस ने 21,707 एफआईआर दर्ज की हैं और 32,903 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2,533 सप्लायर शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,446 किलो हेरोइन, 475 किलो अफीम, 25 टन भुक्की, 35 किलो चरस, 511 किलो गांजा, 12 किलो आईसीई, 3.6 किलो कोकीन, 39.29 लाख नशीली गोलियां और 13.39 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

इसके अलावा, एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत पुलिस ने नशा तस्करों की 205 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुनर्वास के तहत पंजाब पुलिस ने 62,000 लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों या ओएटी केंद्रों में भेजा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के 'Safe Punjab' व्हाट्सऐप चैटबॉट (9779100200) पर प्राप्त सूचनाओं में से 33 प्रतिशत पर कार्रवाई की गई है, और जनता से मिली जानकारी के आधार पर 7,285 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशा तस्करों के बारे में बिना किसी डर के इस चैटबॉट पर गुप्त रूप से जानकारी साझा करें।

इस बैठक में पुलिस आयुक्त अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डीआईजी फिरोज़पुर रेंज नीलांबरी जगदले, डीआईजी बॉर्डर रेंज नानक सिंह, डीआईजी एजीटीएफ गुरमीत चौहान, एसएसपी तरनतारण रवजोत कौर ग्रेवाल और एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

विरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पत्रकार प्रभाकर सम्मान से सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अखिल भारतीय मजदूर संघर्ष समिति के वार्षिक उत्सव समारोह नरेला औधोगिक क्षेत्र में आयोजन किया गया मजदूरों को सम्बोधित करते हुए पत्रकार विरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा आज केन्द्र और दिल्ली सरकार के मजदूर विरोधी कानून के वजह से फैक्ट्री या व्यापारी के द्वारा मजदूर तबके का शोषण किया जा रहा है जिससे बर्दाश्त नहीं किया जा जा सकता चतुर्वेदी ने कहा अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जायेगी मजदूर के हितों के लिए समिति के अध्यक्ष राम निवास पांडे ने पत्रकार प्रभाकर सम्मान से सम्मानित करते हुए कहा विरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी मजदूरो के हित के लिए हमेशा साथ देने के आलावा अपने कलम से भी निर्भीक तौर पर लिखते रहते हैं इसलिए आज इनको सम्मानित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है चतुर्वेदी को शील्ड और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर भारी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित थे चतुर्वेदी ने शील्ड ग्रहण करने के बाद कहा मैं अपने कलम से सच्चाई उजगार करते रहूंगा उन्होंने आज़ के दौड़ में सत्ता के समर्थक पत्रकारिता होने पर निराश जताया।

मिशन सांझा उपराला के तहत बाढ़ प्रभावित स्कूलों गग्गोमाहल और थोबा के विद्यार्थियों में बीबी कोला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट द्वारा 400 स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई

अमृतसर/अजनाला*14 अक्टूबर (साहिल बेरी)

मिशन चढ़दीकला के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी द्वारा शुरू किए गए "मिशन सांझा उपराला" के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के आह्वान को स्वीकार करते हुए विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थाएं पीड़ितों के पुनर्वास में जुट गई हैं और दिन-रात काम कर रही हैं।

इसी के तहत आज ज़िला शिक्षा अधिकारी (से. शि.) श्री राजेश शर्मा और जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी अमृतसर के सचिव श्री सैमसन मसीह के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्था बीबी कोला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट अमृतसर ने आगे आकर सहायता प्रदान की।

इस मुहिम के अंतर्गत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गोमाहल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोबा और सरकारी हाई स्कूल लखूवाल में कुल *400 स्कूल बैग और स्टेशनरी* वितरित की गई।

सामग्री वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के विशेष वक्ता *भाई हरविंदरपाल सिंह लिटिल वीर जी* ने बताया कि ट्रस्ट के प्रमुख सेवक *भाई गुरइकबाल सिंह जी* की अगुवाई में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन, चारपाइयां, बिस्तर, राशन, दवाइयां और अन्य ज़रूरी वस्तुएं लगातार वितरित की जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय यह संस्था अब तक लगभग *1000 स्कूल बैग और स्टेशनरी* वितरित कर चुकी है और आगे भी इसी तरह स्कूलों में बैग व स्टेशनरी का वितरण जारी रहेगा।

इस मौके पर गग्गोमाहल स्कूल के लेक्चरर *प्रीतपाल सिंह, थोबा स्कूल के इंचार्ज **रवदीप सिंह, सरकारी हाई स्कूल लखूवाल के इंचार्ज **रणजीत सिंह भुल्लर, **पंकज सिंह, **मंदीप सिंह भोला, **डॉ. परमजीत सिंह रिंकू, **जतिंदर सिंह, **स्वर्णजीत कुमार, **जोया सचदेवा, **रेखा सरीन, **पुष्पिंदर सिंह, **मेजर सिंह* आदि ने ट्रस्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि ट्रस्ट द्वारा भेंट की गईं नई कॉपियां, किताबें, बैग और अन्य स्टेशनरी सामग्री से बाढ़ प्रभावित स्कूलों के बच्चों को अपनी पढ़ाई फिर से जारी रखने के लिए नया उत्साह मिला है।

मोहकमपुरा क्षेत्र में ड्रग तस्कर की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को किया गया ध्वस्त

अमृतसर, 14 अक्टूबर (साहिल बेरी)

माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नशा तस्करी के खिलाफ जारी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत, जिला प्रशासन अमृतसर द्वारा आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई। थाना मोहकमपुरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक ड्रग तस्कर की अवैध रूप से निर्मित संपत्ति को नगर निगम अमृतसर की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई रोहित सिंह उर्फ कालू पुत्र जसपाल सिंह, निवासी प्यारा सिंह सरपंच चौक, मोहकमपुरा (उम्र २२ वर्ष) के खिलाफ की गई है। रोहित सिंह उर्फ कालू नशा तस्करी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और वर्तमान में जेल में बंद है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कुल चार मामले दर्ज हैं।

उसके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है:

1. एफआईआर नंबर 78, दिनांक ०२.07.२०२२, धारा २१/२९/61/85 NDPS एक्ट, थाना मोहकमपुरा अमृतसर।
2. एफआईआर नंबर 10, दिनांक २४.01.२०२४, धारा २१/२९/61/85 NDPS एक्ट, थाना मोहकमपुरा अमृतसर।
3. एफआईआर नंबर १२, दिनांक २९.01.२०२४, धारा २१/२९/61/85 NDPS एक्ट, थाना मोहकमपुरा अमृतसर।
4. एफआईआर नंबर २३, दिनांक १२.03.२०२५, धारा २१/२९/61/85 NDPS एक्ट, थाना मोहकमपुरा अमृतसर।

आज की कार्रवाई के दौरान नशा तस्कर की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति — जो मोहकमपुरा में स्थित थी — को नगर निगम अमृतसर की टीम ने ध्वस्त कर दिया। यह कदम राज्य सरकार द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान का हिस्सा है। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने इस वर्ष NDPS एक्ट के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक कुल 1138 मामले दर्ज कर १133 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने निम्नलिखित बड़ी बरामदगियां कीं —

१50.5२1 किलोग्राम हेरोइन
२9.65२ किलोग्राम अफीम
3२5.577 किलोग्राम नशीला पाउडर
अन्य विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ
२.88 करोड़ हवाला/ड्रग मनी
96 वाहन, जो तस्करी में उपयोग किए गए

ये लगातार की जा रही कार्रवाइयाँ अमृतसर पुलिस की इस दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि नशा तस्करी को हर कीमत पर समाप्त किया जाएगा और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023